शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 15 अंक : 8 1 मार्च 2023

फाल्गुन-चैत्र मास, विक्रम संवत् 2079

संस्थापक
स्व. मुकुन्दराव कुलकर्णी

❖

परामर्श
के.नरहरि
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
जगदीश प्रसाद सिंघल
शिवानन्द सिन्दनकेरा
जी. लक्ष्मण

❖

सम्पादक
डॉ. शिवशरण कौशिक

❖

सह सम्पादक
भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल
प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय
डॉ. ओमप्रकाश पारीक
डॉ. एस.पी. सिंह
डॉ. दीनदयाल गुप्ता

❖

प्रबन्ध सम्पादक
महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक
बजरंग प्रसाद मजेजी

❖

प्रेषण प्रभारी : **नौरंग सहाय 'भारतीय'**

❖

कार्यालय प्रभारी : **आलोक चतुर्वेदी**

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राजस्थान) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली - 110053
दूरभाष : 8920959986

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

वार्षिक शुल्क ₹ 250/-
दस वर्षीय शुल्क ₹ 2000/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा चित्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ❑ प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल

व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष रूप से व्यापार में कौशल विकास, भारत के लिए एक आवर्ती और तेजी से बढ़ती हुई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में उभरा है। इसलिए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे स्कूलों में कौशल शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जो समग्र शिक्षा के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलुओं को छूते हैं और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति पदानुक्रम को दूर करते हैं। भारत व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और मुख्यधारा में लाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों को लागू करने की राह पर है।

4

अनुक्रम

3.	सम्पादकीय	–	डॉ. शिवशरण कौशिक
8.	व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण कुछ वैश्विक उदाहरण	–	राजेश कुमार जांगिड़
11.	व्यावसायिक शिक्षा : पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण	–	डॉ. नन्द किशोर
15.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा	–	अरुण कुमार मिश्रा
17.	व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियाँ	–	डॉ. जसपाल सिंह वरवाल
19.	व्यावसायिक शिक्षा और सामूहिक उद्यमिता विकास	–	डॉ. शिवशरण कौशिक
23.	व्यावसायिक शिक्षा के विविध संदर्भ	–	डॉ. लक्ष्मीनारायण बेहेरा
25.	Vocational Education and Traditional ...	–	Dr. T.S. Girishkumar
31.	Professional Education and National ...	–	Prof. Suneel Kumar
34.	जी-20 अध्यक्षता का वैश्विक दृष्टिकोण	–	डॉ. हरनाम सिंह
39.	देशप्रेम के संस्कार देता भारत माता नमन स्थल	–	संदीप जोशी

Empowering Youth Through Vocational Education

❑ **Darshan Bharti**

Education is a centrally learner-driven process and it has to be because education aims to allow an individual to gradually reach perfection in all four spheres – physical, psychical, social, and spiritual. Hence in the neohumanist paradigm, P R Sarkar highlights the following crucial issues related to the students which need proper attention while framing policies related to education – Firstly, he holds it is improper to extort anything from students through undue pressure and intimidation. Intimidation appears to work to some extent, but it does not yield lasting results.

28

भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएँ

संपादकीय

डॉ. शिवशरण कौशिक
सम्पादक

भारतीय समाज में शिक्षक का सम्मान पहले की तुलना में भले ही कम हुआ हो, लेकिन शिक्षक से समाज की अपेक्षाएँ आज भी वही हैं जो गुरुकुल के शिक्षकों से की जाती थी। यह कहा जा सकता है कि समाज के अचेतन समूह- मन में यह बात आज भी बैठी हुई है कि समाज में नैतिक मूल्यों की रक्षा और उनकी निर्बाध स्थापना का दायित्व शिक्षक का ही है। इसीलिए समाज शिक्षक से सदैव एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है। आज जब शिक्षा को कौशलाधारित तथा रोजगारपरक बनाने की दिशा में बृहत् स्तर पर कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर युवा शिक्षार्थी के लिए व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन का महत्त्व भी अत्यधिक बढ़ा है। आज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा को सर्वथा रोजगार-प्रदाता अथवा व्यवसायपरक होने के मानदंडों पर ही देखा-परखा जाता है।

अब एक और तथ्य हमारे सामने है कि हमने प्राय: शिक्षण संस्थाओं के मुख्य द्वार पर 'ज्ञानार्थ प्रवेश : सेवार्थ प्रस्थान' लिखा देखा है, यह दोनों सूत्र अब प्रथमदृष्टया एक नारे से अधिक कुछ नहीं लगते, किंतु यही प्रमुख सूत्र हैं जो शिक्षक के नैतिक-बोध और मूल्यों के बुनियादी आचरण की ओर संकेत करते हैं। 'ज्ञान के लिए प्रवेश और सेवा के लिए प्रस्थान' एक आदर्श अवधारणा है। संभवतया इसीलिए 'ज्ञानार्थ' की सीमा में पहले सभी प्रकार के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान के क्षेत्रों की निपुणता के लिए ही 'ज्ञानार्थी प्रवेश' की संज्ञा दी जाती थी। अब 'विद्या' का स्थानापन्न 'शिक्षा' हो गया है जिसकी अपनी अर्थ-संस्कृति और कार्य-संस्कृति भी विकसित हुई है।

इस प्रक्रिया में दूसरा सूत्र आता है 'सेवार्थ प्रस्थान'। इसका अर्थ यही है कि सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण के पश्चात विद्यार्थी अपनी संस्था से बाहर जाने के बाद अपने परिवार, समाज और अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी हो! ऐसी अपेक्षा होती है। अर्थात् उसने अपनी शिक्षा प्राप्त करते समय कुछ ऐसे शिल्प-कौशल विकसित किए होंगे तथा जीवन मूल्य सँजोए होंगे जिनके पालन से उसका नैतिक तथा सांस्कृतिक परिष्कार हो सके।

बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक ऐसी अनुशंसाएँ हैं जो भारत केंद्रित शिक्षा पर आधारित हैं तथा जिनका उद्देश्य भारतीयता की स्थापना करना और इसी के साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप उन्नत बनाना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अनुसार भारत में 19 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के 5 प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त थे। यदि इसकी तुलना अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे संपन्न देशों से की जाए तो यही आंकड़ा उन देशों में क्रमश: 52 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 96 प्रतिशत था। इसका कारण यह था कि अब तक उच्च माध्यमिक स्तर पर भारत में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को केवल औपचारिक रूप में चलाया जाता रहा। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा की समतुल्यता के साथ उच्च शिक्षा में उनके अनुकूल पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जना सुनिश्चित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व वर्णित व्यावसायिक शिक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों के 5 प्रतिशत की संख्या को बढ़ाकर 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों तक ले जाने का उद्देश्य रखा गया है। विद्यालयी शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में इन्हीं के समतुल्य व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। आज विद्यार्थियों की अकादमिक क्षमताओं तथा व्यावसायिक क्षमताओं के चरणबद्ध विकास की बात का भी नीति में प्रस्ताव है। विद्यालय स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा में समान रूप से व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को समेकित करने का भी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है। इसे तकनीकी संस्थान जैसे - आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग तथा कुछ कौशलाधारित निजी संस्थानों के सहयोग से क्रियान्वित करने का सुझाव दिया गया है। इन सबके बीच में समन्वय और सहयोग की रूपरेखा भी तैयार की जानी चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय के आसपास के अन्य विद्यालय भी किसी उन्नत प्रयोगशाला में एक साथ कार्य कर लाभ उठा सकते हैं। इस क्रम में कौशल आधारित प्रयोगशालाओं की साधन-संपन्न विद्यालय में स्थापना के साथ विद्यार्थी एक दूसरे के विद्यालय में जाकर अपना विकास कर सकते हैं । नीति में भारत के स्थानीय ज्ञान, स्थानीय हस्तशिल्प आदि के महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित करने की प्रबल संभावना होगी। अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में एकीकृत किया जाकर विद्यार्थियों का कौशल-विश्लेषण करना होगा और आवश्यकताओं के मानचित्रण के साथ व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र का चयन करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति 'नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन' के गठन की बात कही है जिसमें विशेषज्ञों द्वारा भारत की जनसंख्या के अनुपात में इसे एक बड़ा निवेश मानती है। कहा गया है कि हमारे देश की जनसंख्या यदि कुशल है तो देश भर में कुशल नागरिकों के निर्माण के साथ-साथ कुशलता की आवश्यकताओं की पूर्ति भारत कर सकता है लेकिन तभी संभव है जब हमारे कौशल विकास कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रयोगशाला तथा कार्यशालाएँ निर्मित व स्थापित करनी होंगी। इस सब के साथ-साथ पूरी पाठ्यचर्या का पुनर्निमाण होना भी उतना ही आवश्यक है। ❑

व्यावसायिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति

प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल
कुलपति
गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के आने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का अहम सिलसिला शुरू हो गया है। इस नीति में पठन-पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधारित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी केंद्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर जोर दिया गया है जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और उनकी रचनात्मक क्षमता भी विकसित की जा सके। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धांत पर बल दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए या फिर विद्यार्थियों में विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान खोजने तक ही सीमित न रहें बल्कि शिक्षा से सामाजिक और भावात्मक कौशल का विकास भी हो इन्हें सॉफ्टस्किल्स कहा जाता है। इनमें सांस्कृतिक चेतना और अनुभूति, दृढ़ निश्चय और विश्वास, टीम भावना, नेतृत्व और संचार क्षमता जैसे गुणों का विकास भी शामिल है।

भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि – ''आज के युवा, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, भारत की आजादी के 100 वर्ष तक भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए इस नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है यह आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है।''

ऐतिहासिक रूप से 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद से स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है और माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना, 1988 में शुरू की गई थी। बुनियादी ढाँचे, वित्त और नीति में विभिन्न बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, योजना को 2011 में संशोधित किया गया था। इसके बाद 2014 में इसमें फिर से संशोधन किया गया जिसका विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना, युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना, शिक्षित तथा रोजगार योग्य लोगों के बीच की खाई को पाटना और अकादमिक उच्च शिक्षा पर दबाव कम करना है। वर्तमान में, इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना

'समग्र शिक्षा' के हिस्से के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के साथ जोड़ा गया है। व्यावसायिक विषयों को माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में सरकारी स्कूल तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं।

इस परिकल्पना का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य लाखों बच्चों को उनके स्कूल के वर्षों में एकीकृत और समग्र तरीके से कौशल शिक्षा प्रदान करना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 14,435 विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन पिछले 6 वर्षों में लगभग 10 गुना बढ़ा है। देशभर में व्यवसायिक शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या 2014-15 में केवल 960 थी, जो 2021-22 में बढ़कर 11,710 हो गई है।

वर्तमान में,1.5 मिलियन से अधिक विद्यार्थी अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में एक भाग के रूप में समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें एक प्रशिक्षित प्रशिक्षक की मदद से स्कूल में ही विषय विशिष्ट प्रयोगशाला में सीखने की सुविधा प्रदान की जाती है। कृषि, मोटर वाहन, सौंदर्य तथा आरोग्य, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी/आईटीईएस, मीडिया तथा मनोरंजन, नलसाजी, खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य आदि जैसे 20 क्षेत्रों से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 62 व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

सीबीएसई भी व्यवसाय-शिक्षा को समग्र शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण घटक मानता रहा है। सीबीएसई द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए स्कूलों और विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक योग्यता-आधारित पाठ्यक्रमों में से चुनने के लिए व्यापक विकल्प प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों सहित, देश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 35लाख विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रम ले रहे हैं।

जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेख किया गया है, ''शिक्षा का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि चरित्र निर्माण और 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तियों का निर्माण करना होगा।'' यद्यपि स्कूलों में कौशल शिक्षा इस उद्देश्य की दिशा में एक साधन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का भी उल्लेख किया है जैसे व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी कथित सामाजिक स्थिति पदानुक्रम और एक 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की मुख्य धारा के साथ इसके एकीकरण की कमी आदि।

व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष रूप से व्यापार में कौशल विकास, भारत के लिए एक आवर्ती और तेजी से बढ़ती हुई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में उभरा है। इसलिए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे स्कूलों में कौशल शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जो समग्र शिक्षा के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलुओं को छूते हैं और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति पदानुक्रम को दूर करते हैं। भारत व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और मुख्यधारा में लाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों को लागू करने की राह पर है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसलिए यह भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे वह कम से कम एक व्यवसाय सीख सकें तथा अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल करके उन्हें कई और व्यवसायों में शामिल कर सकें। महत्त्वपूर्ण रूप से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न मॉडलों को भी प्रोत्साहित करती है ताकि स्थानीय रूप से प्रासंगिक कौशल शिक्षा को उचित तरीके से पेश किया जा सके।

व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के किसी भी कार्यक्रम के लिए बच्चे को किन में रखने और उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे परिणामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए स्कूलों के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक) पर उम्र के अनुरूप और अनुकूलित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

उच्च प्राथमिक स्तर में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एक क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल के साथ खुद के अनुकूलन के अवसर प्रदान करना और उन्हें उच्च कक्षाओं में अपने विषयों का चयन करने में सक्षम करना है। कक्षा 6 से 8 तक शुरू किया जाने वाला पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम मुख्य रूप से गतिविधि आधारित शिक्षण-लर्निंग पर केंद्रित होगा। यह न केवल किताबी ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान के बीच की सीमाओं को कम करेगा, बल्कि बच्चों को कार्य क्षेत्रों में कौशल आवश्यकताओं के

बारे में जानकारी देगा, इस प्रकार उन्हें भविष्य के पेशे के बारे में फैसला लेने में मदद करेगा। इन गतिविधियों से सुरुचिपूर्ण मूल्यों, सहयोग, टीम वर्क, कच्चे माल का विवेकपूर्ण उपयोग, रचनात्मकता, गुणवत्ता चेतना आदि जैसे सॉफ्ट स्किल्स के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। गतिविधि आधारित शिक्षा के माध्यम से हाथ से किए जाने वाले काम की सराहना और श्रम को सम्मान के संबंध में वांछनीय दृष्टिकोण और मूल्य विकसित किए जाएंगे, जहाँ टीमवर्क और सहयोग से अनुशासन, दृढ़ता और रचनात्मकता प्राप्त की जाएगी। इसका कार्यान्वयन स्कूल या सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों के साथ किया जा सकता है, साथ ही सभी विषयों को नियमित शिक्षकों द्वारा सुगम बनाया जा सकता है, इस प्रकार इसे बड़े पैमाने पर आसानी से दोहराया जा सकता है।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, विद्यार्थियों को अन्य शैक्षणिक विषयों के साथ राष्ट्रीय कौशल योजना फ्रेमवर्क के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। एनएसक्यूएफ एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित ढाँचा है और ज्ञान, कौशल तथा रुझान के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता की योजना बनाता है। विद्यार्थी न केवल स्कूल की प्रयोगशाला में किसी विशेष क्षेत्र में व्यावसायिक कौशल सीखने में संलग्न होते हैं, बल्कि अतिथि व्याख्यान और क्षेत्र के दौरे के अलावा इंटर्नशिप/नौकरी के दौरान प्रशिक्षण में भाग लेकर विशेष व्यवसाय का वास्तविक जीवन अनुभव भी प्राप्त करते हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अन्य शैक्षणिक विषयों के समान माना जाए और विषयों की योजना में समान दर्जा दिया जाए। अब संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल से युक्त रोजगार कौशल माड्यूल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है।

उच्च प्राथमिक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण, व्यावसायिक शिक्षा को 'एप्लाइड लर्निंग' के रूप में बदलने में मदद करता है और साथ ही उन्हें बहुत आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करता है। इस प्रकार उन्हें भविष्य में उच्च शिक्षा रोजगार या आजीविका के लिए तैयार करता है।

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संबोधित करने का लक्ष्य रखा गया है, वह है सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। इसे सक्षम करने के लिए, अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और दोनों के बीच गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत क्रेडिट संचय और हस्तांतरण ढाँचा तैयार किया जा रहा है। यह व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक आकांक्षी बनाने में मदद करेगा और दोनों के बीच अत्यधिक अलगाव को दूर करेगा।

व्यावसायिक शिक्षा में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को शामिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में, आइए उन मॉडलों को देखें जो इस आयु वर्ग के व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समग्र शिक्षा के तहत, व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए हर साल नए स्कूलों को मंजूरी दी जा रही है और उन्हें अपने परिसर में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा 'हब एंड स्पोक' मॉडल लागू किया जा रहा है जहाँ अपेक्षित बुनियादी ढाँचे वाले स्कूल हब के रूप में कार्य करेंगे और आसपास के स्पोक स्कूलों के बच्चों को कौशल शिक्षा प्रदान करेंगे। योजना के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे हब के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ-साथ हब और उसके स्कोप के बीच बच्चों के परिवहन की सुविधा के लिए धन प्रदान किया जाता है।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने में प्रमुख भागीदार हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा राष्ट्रीय नीति को उचित रूप से अपनाना

और लागू करना महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न घटकों को पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सेक्टर कौशल परिषद जैसी राष्ट्रीय एजेंसी/संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

इसी तरह, स्थानीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान; पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ सामग्री, डिजिटल शिक्षण सामग्री आदि के अधिग्रहण और विकास के साथ-साथ स्कूल स्तर पर कौशल शिक्षा प्रदान करने में लगे व्यावसायिक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों जैसे राज्य व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और इसके अधीनस्थ निकायों को सक्षम बनाया जा सकता है। विविधता और स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान के सिद्धान्त पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फोकस को ध्यान में रखते हुए इन संगठनों के संदर्भ में राज्यों का क्षमता निर्माण अनिवार्य हो जाता है।

कौशल शिक्षा को लगातार बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखने और इसे विद्यार्थियों, उद्योग तथा समुदायों के लिए प्रासंगिक बनाए रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के अनुरूप विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए कौशल पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रभावी बने रहने चाहिए।

कुशल जनशक्ति की आपूर्ति यदि उद्योग या काम की दुनिया में माँग के साथ मेल खाती है तो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या कौशल कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकेगा। इसलिए ज्ञान और कौशल के लिए उभरती आवश्यकताओं का आकलन करना और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण या कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से उनका मिलान करना महत्त्वपूर्ण है।

भविष्य के कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है वह है आईटी/आईटीईएस, अक्षय ऊर्जा/हरित ऊर्जा, बिजली, आतिथ्य, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित निर्माण, सतत खनन, हरित, दूरसंचार, हरित कृषि, डिस्पोजेबल प्लास्टिक और रसायन आदि।

21वीं सदी के कौशल के अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे उभरते रुझानों को तलाशने की जरूरत है डिजिटल स्केल इन सभी कौशल विकास गतिविधियों का मुख्य कार्यक्रम बनना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रणाली को विकसित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षण को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सके और इसकी पहुँच को बढ़ाया जा सके। हमें क्लाउड कंप्यूटिंग, गैमीफिकेशन के माध्यम से कोडिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3डी प्रिंटिंग) ऑपरेटर, लो वोल्टेज ईवी सर्विस टेक्निशियन, टेलीमैटिक्स डाटा एनालिस्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसे भावी कौशल पर भी काम करने की जरूरत है। सीबीएसई पहले ही डाटा साइंस, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे पाठ्यक्रम शुरू कर चुका है।

विद्यार्थी जब स्कूल से निकलकर उच्च शिक्षा, रोजगार या आजीविका में जाएंगे तब कौशल शिक्षा के परिणाम आएंगे। महत्त्वाकांक्षी पेशे की ओर बढ़ने के लिए व्यवसाय कौशल के बारे में उपलब्ध रास्ते और कॉरिअर परामर्श के बारे में विद्यार्थियों, उद्योगों और संस्थानों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ''व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष रूप से व्यापार में कौशल विकास, भारत के लिए एक आवर्ती और तेजी से बढ़ती हुई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में उभरा है।'' इसलिए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे स्कूलों में कौशल शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जो समग्र शिक्षा के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलुओं को छूते हैं और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति पदानुक्रम को दूर करते हैं। भारत व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और मुख्यधारा में लाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों को लागू करने की राह पर है। साथ ही, सभी स्तरों पर हितधारकों की भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चों को 21वीं सदी के लिए आवश्यक व्यावसायिक और जीवन कौशल प्राप्त हो सके। ❑

व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण कुछ वैश्विक उदाहरण

राजेश कुमार जांगिड़
आचार्य,
पंजाब केंद्रीय
विश्वविद्यालय, बठिंडा

व्यावसायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यकारी समूह के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक व अनौपचारिक कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा व कौशल विकास के प्रयास सम्मिलित हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में एक उद्देश्य विद्यार्थी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

यह आत्मनिर्भरता मजदूरी रोजगार या स्वरोजगार के रूप में हो सकती है। इसके लिए विद्यार्थियों को कौशल युक्त बनाने तथा उनमें उद्यमिता के विकास के प्रयास किए जाते हैं। मानव विकास के अनेक आयाम हैं जिनमें शारीरिक, मानसिक, नागरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पक्ष सम्मिलित हैं। आर्थिक आयाम में व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक विकास, रोजगार युक्त होना, उद्यमिता विकास व निर्धनता निवारण सम्मिलित हैं।

व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के उद्देश्यों में विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ण करने, निर्धनता व बेरोजगारी को हटाने, उत्पादकता वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था के गतिशील क्षेत्रों को दक्ष व कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराना होता है। जनसंख्या के बड़े भाग को व्यवसाय शिक्षा की ओर आकर्षित करना ताकि सामान्य शिक्षा की ओर जाने का चलन कम हो तथा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने वाली व लाभदायक रोजगार प्रदान करने वाले प्रशिक्षण की स्थापना हो सके।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर प्रशिक्षण के संबंध में औपनिवेशिक काल व स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समितियों व आयोगों द्वारा निम्न अनुशंसा की गई।

वुड्स डिस्पैच (1854) ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करने पर बल दिया। हंटर आयोग (1882) ने शिक्षा की समस्या में पहली बार व्यावसायिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया। हरतर्ग पुनरीक्षण समिति (1924) तथा सप्रू जांच समिति (1934) ने देश के आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। वुड्स एबोट सलाहकारी समिति रिपोर्ट (1936) के आधार पर पॉलिटेक्निक शिक्षा स्थापित की गई। सार्जेंट रिपोर्ट (1944) ने अकादमिक व तकनीकी शिक्षा की दो धाराओं की शुरुआत की बात की। आजादी के पश्चात राधाकृष्णन समिति (1948) ने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में

व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण जो सही शिक्षा में इस तरह के पाठ्यक्रम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं जैसे तकनीकी कौशल प्राप्त कर श्रम बाजार में प्रवेश चाहने वाले, प्रौढ़ जो अपने को अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए अपना कौशल बढ़ाना चाहते हैं तथा छात्र जो अकादमी पाठ्यक्रमों में बीच में छोड़ देने का अधिक जोखिम रखते हैं। व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा वैश्विक दुनिया में अपने कौशल विकास कर जनसंख्या में तकनीकी रूप में दक्ष लोगों की संख्या बढ़ाकर अपने को प्रतियोगी रखते हुए आर्थिक विकास को तेज करना चाहते हैं के लिए आवश्यक है।

व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित करने पर बल दिया। मुदलियार कमिशन (1952) ने कक्षा 11 के स्तर पर बहुउद्देश्य विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। इसमें 8 वर्ष की शिक्षा के बाद विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई। कोठारी कमीशन (1964-66) रिपोर्ट में कक्षा 8 तक वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम व माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों पर बल दिया। कैब कमेटी ने एनसीईआरटी को व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की भूमिका प्रदान की।

व्यावसायिक शिक्षा पर कार्यकारी समूह (1977) ने व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य परिषद की स्थापना की अनुशंसा की। मेल्कम कमेटी (1977) ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षकों के लिए भर्ती नीतियों तथा उपयुक्त वर्टिकल मोबिलिटी की अनुशंसा की। 1986 की शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही व इसमें आजीवन शिक्षा तथा लोचशील विधियों द्वारा शिक्षा की अवधारणा पर बल दिया गया।

आजादी से पूर्व तथा आजादी के पश्चात उपर्युक्त समितियों में आयोगों की सिफारिशों व अनुशंसाओं के पश्चात भी भारत में कुशल श्रम शक्ति का तीव्र अभाव देखा गया।

देश में औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षित का 2 प्रतिशत व अन्य 10 प्रतिशत की तुलना में कोरिया में 98 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत तथा जर्मनी में 75 प्रतिशत भारत में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण की दीर्घकालीन उपेक्षा को इंगित करता है। भारत में रोजगार गारंटी का प्रति परिवार 100 दिन अकुशल रोजगार देने वाला कार्यक्रम भारत के श्रम शक्ति की कौशल युक्त होने के अभाव का स्पष्ट चित्रण करता है। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण का स्तर बहुत सी समस्याओं से युक्त होने के साथ-साथ असंतोषप्रद था। एक ओर प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार का अभाव था तथा दूसरी ओर नियोजकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षित व दक्ष लोगों की कमी महसूस हो रही थी।

व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के कुछ मॉडल

जर्मनी - जर्मनी में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण में विद्यालय में कक्षा कक्ष अध्ययन व उद्योगों से अप्रेंटिसशिप का संयुक्त रूप विद्यमान है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षु सप्ताह में एक या दो दिन व्यवसाई पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पहलू व सामान्य शिक्षा का स्कूल में अध्ययन करता है। बाकी दिनों वे उद्योगों की वास्तविक कार्य स्थिति में व्यावसायिक प्रायोगिक कौशल प्राप्त करते हैं। कार्यस्थल-प्रशिक्षण की लागत उद्योगों द्वारा वहन की जाती है तथा विद्यालय की लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में केवल उद्योग ही नहीं अपितु

व्यावसायिक संगठन भी सक्रिय सहभागिता करते हैं। प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षु व प्रशिक्षण देने वाली फर्मों के बीच अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण समझौते की व्यवस्था है जो दोनों के बीच प्रशिक्षण अवधि के दौरान संबंधों का आधार बनता है। कार्यस्थल व्यावसायिक प्रशिक्षण उद्योगों के प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा व्यावसायिक संगठनों की देखरेख व निरीक्षण में किया जाता है। प्रशिक्षण की यह व्यवस्था देश के कानूनों द्वारा शासित व नियमित होती है। इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिनियम 1969 तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पदोन्नति अधिनियम 1981 बने हुए हैं। विद्यार्थी के व्यावसायिक कौशल व प्रशिक्षण की परीक्षा व प्रमाणन प्रशिक्षण देने वाला उद्योग द्वारा व्यावसायिक संगठनों के निरीक्षण में की जाती है। सामान्य शिक्षा व सैद्धांतिक परीक्षा का मूल्यांकन लिखित परीक्षा रूप में विद्यालय शिक्षकों द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण की अवधि, प्रकृति व आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग है। स्कूलों में सैद्धांतिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ भाषा सामान्य अध्ययन, धर्म, अर्थशास्त्र व खेलकूद का अध्यापन होता है। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण में उद्योगों की संलग्नता केवल प्रशिक्षण देने में नहीं अपितु पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात मूल्यांकन में भी होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण व्यावसायिक दक्षता के मानकों पर आधारित है। जर्मनी में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कानूनी आधार बनाए गए हैं। इस प्रशिक्षण व्यवस्था ने नियोजकों, प्रशिक्षकों व राष्ट्र को प्रभावी परिणाम व लाभ उपलब्ध कराए हैं।

ऑस्ट्रेलिया - ऑस्ट्रेलिया ने अपने आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने, आवश्यकता के अनुरूप कुशल श्रम बल सृजित करने के लिए प्रभावी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण की दिशा में प्रयास किया है। ऑस्ट्रेलिया में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण 10 वर्ष विद्यालय शिक्षा में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात आरंभ होता है। 1970 में टेक्निकल एंड फॉरवर्ड एजुकेशन व्यवस्था लागू होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण को स्कूल क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। 1990 में केंद्र सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलियाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई जिसका कार्य व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए नीति बनाना तथा कार्यक्रमों की देखरेख करना है। इस व्यवस्था में कार्यस्थल से भिन्न व कार्यस्थल पर दोनों तरह के व्यवसाय प्रशिक्षण की व्यवस्था है। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण में टेक्निकल एंड फॉरवर्ड एजुकेशन तथा निजी आपूर्तिकर्ता दोनों सहयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के संबंध में नीति निर्माण का कार्य करती है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण, व्यावसायिक मानकों की स्थापना, मूल्यांकन व प्रत्यायन का कार्य सम्मिलित है। यह एक उच्च अधिकार प्राप्त संस्थान है जो राज्य मंत्रियों की परिषदों तथा उद्योग प्रशिक्षण सहकारी बोर्डों से सहायता लेता है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य ने व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण को निम्न पहलुओं में महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। यह पूर्ति पक्ष से प्रेरित होने की अपेक्षा माँग पक्ष की ओर प्रेरित हो रहा है, कक्षा-कक्ष अध्यापन से कार्यस्थल प्रशिक्षण की ओर प्रशिक्षण, उद्योगों के लिए कौशल प्रशिक्षण की अपेक्षा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कौशल विकास पर बल, कार्य पूर्व प्रशिक्षण से जीवन पर्यंत प्रशिक्षण की ओर, निश्चित प्रशिक्षण से लोचशील प्रशिक्षण की ओर, कठोर फ्रेम वर्क से बहु प्रवेश व निकास व्यवस्था की ओर तथा सरकार द्वारा वित्तीय से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर परिवर्तन ही रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण जो सही शिक्षा में इस तरह के पाठ्यक्रम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं जैसे तकनीकी कौशल प्राप्त कर श्रम बाजार में प्रवेश चाहने वाले, प्रौढ़ जो अपने को अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए अपना कौशल बढ़ाना चाहते हैं तथा छात्र जो अकादमी पाठ्यक्रमों में बीच में छोड़ देने का अधिक जोखिम रखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा वैश्विक दुनिया में अपने कौशल विकास कर जनसंख्या में तकनीकी रूप में दक्ष लोगों की संख्या बढ़ाकर अपने को प्रतियोगी रखते हुए आर्थिक विकास को तेज करना चाहते हैं, के लिए आवश्यक है। 2013 के बाद निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के देशों ने अपनी व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण बदला है। एक, पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाकर व शिक्षक गुणवत्ता वृद्धि द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समग्र गुणवत्ता बढ़ाना। दो, व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण में पहुँच को बढ़ाना तथा इसे विद्यार्थियों के लिए आकर्षक बनाना तथा तीन, उपलब्ध स्थान, कार्यस्थल प्रशिक्षण तथा रोजगार संलग्नता को बढ़ावा देकर कार्यस्थल प्रशिक्षण को मजबूत करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के प्रावधान भारत में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण की समस्या व चुनौतियाँ को हल करने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की जनांकिकी लाभ की स्थितियों के परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण व प्रभावी प्रयास प्रतीत होता है। ❑

व्यावसायिक शिक्षा : पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण

डॉ. नन्द किशोर

शिक्षक शिक्षा विभाग,
शिक्षा पीठ,
केंद्रीय विश्वविद्यालय
हरियाणा

शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का सशक्त साधन हैं जिसमें उसकी अपनी आत्मनिर्भरता भी सम्मिलित है- यदि हम कल्पना करें कि शिक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात एक भी जीविकापूर्ण कार्य का विकल्प हाथ में न आए तो हमारी स्थिति क्या होगी? हमारा क्या अस्तित्व होगा? इस पर विचार करना आवश्यक है और जीवन में सुख शान्ति की स्थापना के लिए शिक्षा को मानवतावादी के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी बनाना अनिवार्य है- इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा अपनी अहम भूमिका निभाती है। व्यावसायिक शिक्षा दो शब्दों के संयोग से निर्मित है। ''व्यवसाय'' शब्द जीविकोपार्जन के लिए अपनाये जाने वाले कारोबार के अर्थ में है तथा शिक्षा-संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षण युक्त सीखने से है। अर्थात व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यवसाय संचालन संबंधी जानकारी प्रदान करती है। जान डी.वी. के अनुसार ''व्यवसायपरक शिक्षा व्यक्तियों को एक विशिष्ट कार्य के योग्य बनाती है, जिससे अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा समाज में विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करता है।'' शिक्षा और व्यवसाय जीविका रूपी रथ के दो पहिए हैं। शिक्षा के बिना जीविकोपार्जन संभव नहीं, व्यवसाय बिना शिक्षा व्यर्थ है। अत: शिक्षा और व्यवसाय एक-दूसरे के पूरक हैं, मानवीय प्रगति के सम्बल हैं, राष्ट्रीय विकास के उपकरण हैं, आर्थिक उन्ति के परिचायक हैं। प्राचीन युग में शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना था। इसलिए सिद्धान्त वाक्य बना 'ज्ञान तृतीय' मनुजस्य नेत्रम् (ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है।) उस समय शिक्षा केवल धनोपार्जन का माध्यम नहीं थी। हाँ 'विद्या अर्थकरी' होनी चाहिए, यह विचार निश्चित ही था। जीवलोक के छह सुखों में 'अर्थकरी विद्या' को भी एक सुख माना गया था।

व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में उसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्थान दिया जाता हैं जो विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन करने योग्य बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का प्रथम प्रयास कोठारी आयोग 1964 ने किया। इस आयोग ने सरकार को माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का सुझाव

दिया। व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को व्यवसाय चुनने एवं व्यवसाय संबंधित योग्यता प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करती हैं। समाज एवं देश में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी समय के साथ परिवर्तन होते हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान की शिक्षा, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना महत्त्वपूर्ण है। आधुनिक युग में मानव संसाधन के रूप में विकास में शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्यकुशल नहीं बन सकता। कार्यकुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता की प्राप्ति नहीं की जा सकती हैं।

बदलते समय के साथ लोगों ने व्यावसायिक (वोकेशनल) शिक्षा के महत्त्व को समझ लिया है। भविष्य में इसके और उन्नत होने की सम्भावना है। निकट भविष्य में नये-नये उद्योग-धन्धों का विकास होना स्वाभाविक है। इस दशा में सभी का प्रशिक्षित और व्यावसायिक रूप से शिक्षित होना नितांत आवश्यक हो जाएगा। शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का सशक्त साधन है। प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था मानव को उच्च आदर्शों की उपलब्धि के लिए अग्रसर करती थी और उसके वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के सम्यक विकास में सहायता करती थी। शिक्षा की यह व्यवस्था हर देश और काल में तत्कालीन सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन सन्दर्भों के अनुरूप बदलती रहती है। शिक्षा का प्रमुख कार्य मनुष्य को ज्ञान, बोध, भाव, सदाचार, तकनीकी कौशल/दक्षता या विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रकार यह कौशलों (skills), व्यापारों या व्यवसायों एवं तंत्रिका विकास, मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। इसकी पुष्टि हेतु हम श्रीमद्भगवदगीता में 'योगकर्मसुकौशलम्' अर्थात् 'कर्म में कुशलता ही योग है' मनुष्य को शिक्षा प्राप्ति के उपरांत आत्मनिर्भर होना चाहिए- शिक्षा लोगों को जीविकोपार्जन के लिए प्रेरित करनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान के बिना, कोई व्यक्ति जीवन के संघर्ष में प्रवेशन नहीं कर सकता है।

इसलिए भारत में सदैव ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में यहाँ लोक प्रिय कहावत के अनुसार खेती को सर्वोत्तम व्यवसाय के रूप में माना जाता रहा है - भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में, भारत की जनसंख्या 136 करोड़ से अधिक है। इस बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त , यदि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता है, तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या केवल हर साल बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम सभी को वैज्ञानिक कृषि यंत्रों का अच्छा उपयोग करने की आवश्यकता है। अपनी व्यावसायिक शक्ति बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक छात्र को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, शिक्षित युवा अधिक सक्रिय और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य भूमि संसाधनों में निवेश करना है। अगर यह धन का अच्छा उपयोग होता है तो देश समृद्ध होगा।

व्यावसायिक शिक्षा जीवन स्तर में सुधार का शिक्षण है। व्यावसायिक शिक्षा जीवन को मधुर बनाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन केवल पुस्तकों के माध्यम से प्रगति नहीं करता है। इसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक शिक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है। इनमें कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी और बढ़ईगीरी आदि इस शिक्षा में शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, युवा भविष्य के जीवन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं यदि इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और पूरी तरह से लागू किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य बहुआयामी है। यह शिक्षा देश की

व्यावसायिक शिक्षा जीवन स्तर में सुधार का शिक्षण है। व्यावसायिक शिक्षा जीवन को मधुर बनाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन केवल पुस्तकों के माध्यम से प्रगति नहीं करता है। इसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक शिक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है। इनमें कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी और बढ़ईगीरी आदि इस शिक्षा में शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, युवा भविष्य के जीवन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं यदि इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और पूरी तरह से लागू किया जाए।

आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मदद करती है। वर्तमान पाठ्यक्रमों में टाइपिंग, बुकबाइंडिंग, बागवानी, कंप्यूटर, सिलाई, मत्स्य पालन, और पहले प्रशिक्षण भी कुछ नौकरियों जैसे वेल्डिंग, बढ़ईगीरी, मोटर वाहन सेवाओं तक ही सीमित था, लेकिन बदलते समय के साथ प्रशिक्षण ने पर्यटन प्रबंधन, खाद्य और पेय प्रबंधन, कंप्यूटर नेटवर्क प्रबंधन, खुदरा प्रशिक्षण, पैरालीगल प्रबंधन और जैसे नौकरी कार्यों की विस्तृत श्रृंखला का विस्तार किया है बहुत कुछ शामिल हैं जिनमें से प्रमुख रूप से निम्नलिखित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण प्रचलित हैं यथा दवा, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिल्म और टीवी, एनिमेशन, आतिथ्य, पत्रकारिता और जनसंचार, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, शिक्षक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, कृषक, लेखा और वित्तकानून, डायटेटिक्स, नागरिक नौसेना, वैमानिकी, फार्मासिस्ट, पर्यावरण विज्ञान, व्यवसाय प्रशासन के परास्नातक, इवेंट मैनेजमेंट, ब्यूटीशियन, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, मानव संसाधन, पर्यटन, संगीत आदि-

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अनुमान के अनुसार 19-24 आयुवर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत (5 प्रतिशत से कम लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की; जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में अत्यंत अधिक 96 प्रतिशत पर यह संख्या काफी अधिक है। यह संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती हैं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,16.1)।

व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्त्व की शिक्षा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्यधारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह एक ऐसी धारणा है जो आज भी जस की तस बनी हुई है, और विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इससे निपटने के इस तथ्य को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है कि भविष्य में विद्यार्थियों के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश किस प्रकार की जाती है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,16.3)। व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों को विभिन्न नौकरियों जैसे कि व्यापार और शिल्प में काम करने के लिए प्रशिक्षित करती है। यह कैरियर और तकनीकी शिक्षा को संदर्भित करता है जो विद्यार्थियों को विशिष्ट कैरियर के लिए तैयार होने में सहायता करता है। व्यावसायिक कार्यक्रम विद्यार्थियों को निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो उन्हें प्रमाणन या डिप्लोमा की ओर ले जाते हैं। व्यावसायिक स्कूल माध्यमिक स्तर, उच्च शिक्षा स्तर और आगे की शिक्षा पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। छात्र प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कार्यक्रम, प्रशिक्षुता और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आदि में से एक चुन सकते हैं। इससे

पहले, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिकांश कार्यक्रम कक्षा में या नौकरी के क्षेत्र में होते थे, हालांकि अब ऑनलाइन व्यावसायिक शिक्षा लोकप्रिय हो गई है और विद्यार्थियों के लिए पेशेवरों से विभिन्न कौशल सीखने का एक आसान विकल्प है। व्यावसायिक शिक्षा विशेष कार्य में निर्देशों पर व्यावहारिक कौशल और सहयोग प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। व्यावसायिक कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य वातावरण मिलता है। व्यावसायिक शिक्षा प्रमुख रूप से विकसित हो रही है और विशिष्ट नौकरियों के लिए कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों को निर्मित करती है।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा के सरकार के उल्लेखनीय कदम में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC): इसका उद्देश्य बड़े, गुणवत्तापूर्ण और लाभकारी व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह उद्यमों, कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को वित्तपोषण प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : यह कई मौजूदा योजनाओं का पुनर्गठन करता है, जिसके पश्चात् उन्हें सिंक्रनाइज तरीके से लागू किया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्त्व की शिक्षा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्यधारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह एक ऐसी धारणा है जो आज भी जस की तस बनी हुई है, और विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान : यह नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ देश की सबसे बड़ी पहलों में से एक है।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन : इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक महत्त्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता कौशल के साथ प्रति परिवार कम-से-कम एक व्यक्ति को सशक्त बनाना था।

निष्कर्ष राष्ट्र निर्माण में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। यही कारण है कि कई लोगों ने प्राथमिक स्तर से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से एक 'माध्यमिक शिक्षा समिति' की स्थापना की है। प्रांतीय सरकारों ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं। व्यावसायिक स्कूलों को सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है। भले ही व्यावसायिक शिक्षा के लिए विभिन्न कठिनाइयाँ हों, राष्ट्र-निर्माण में इस शिक्षा की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस शिक्षा के विकास से देश से बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सकती है। तकनीकी रूप से समझदार नौजवान आत्मनिर्भर बन कर खुद को राष्ट्र-निर्माण की महान धारा में शामिल कर लेता। मशीनरी और कुटीर उद्योगों का प्रसार ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। कुटीर उद्योग में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी प्रयासों की आवश्यकता है। हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा की प्राचीन प्रणाली पर करीब से पता चलता है कि शिष्य उस समय के गुरुकुल शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके उत्तरोत्तर जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावसायिक शक्ति प्राप्त कर रहे थे। हाल ही में, व्यावसायिक शिक्षा को एक नए परिष्कृत रूप में बदल दिया गया है। ❑

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा

अरुण कुमार मिश्रा
सहायक प्राध्यापक
(संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी)
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (यूसेट)
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग (झारखंड)

'शिक्षा क्या है?' इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अनेक विद्वानों ने शिक्षा को परिभाषित किया है। भारतीय सनातन संस्कृति के पुरोधा, महान दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चिंतक स्वामी विवेकानंद ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि व्यक्ति के आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति शिक्षा है। वे ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करते थे जो जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार कर सके। ऐसी शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भर पाती है तथा व्यक्ति को स्वावलंबी बनने में मदद कर पाती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास कर सकने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था मौजूद हो तथा कौशल विकास का समायोजन हो। स्वामी जी मानते थे की ज्ञान तो व्यक्ति में पहले से ही होता है, केवल उपयुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों को व्यवसाय चुनने एवं इससे संबंधित योग्यता प्राप्त कराने में सहायक हो, व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है।

21वीं शताब्दी में भारतवर्ष युवा जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश बनने वाला है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग को पूर्ण करने तथा समावेशी एवं संतुलित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई। 1988 ई. में माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई। वित्त, नीति एवं अन्य बुनियादी ढांचों संबंधित समस्याओं को समझते हुए 2011 में इस योजना को संशोधित किया गया था। पुनः 2014 ई. में इसमें संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के साथ ही साथ युवाओं के अंदर रोजगार की क्षमता को विकसित करना था। वर्तमान में केंद्र प्रायोजित 'समग्र शिक्षा' योजना के अंश के रूप में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय कौशल योगिता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ भी इसे जोड़ा गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 14,435 विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। पूरे भारत में 2021-22 में एक 11,710 ऐसे विद्यालय थे जहाँ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी। यह संख्या 2014-

15 में मात्र 960 थी।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के आकलन के अनुसार औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय युवाओं (19 से 24 आयु वर्ग) का मात्र 5 प्रतिशत था। विकसित देशों यथा संयुक्त राज्य अमेरिका (52 प्रतिशत), जर्मनी (75 प्रतिशत) और दक्षिण कोरिया (96 प्रतिशत) की तुलना में यह संख्या काफी कम है। यह संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता के साथ सम्मुख रखती है। इसी कारणवश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा के नवीन आकल्पन की बात करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में अहम बदलावों का प्रारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप हैं। शिक्षक आधारित शिक्षण व्यवस्था को समय के अनुरूप परिवर्तित करना आवश्यक था। इसलिए विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु यह शिक्षामित्र नीति विद्यार्थी केंद्रित नई व्यवस्था की बात करती है और इसके क्रियान्वयन हेतु समूची प्रणाली में बदलाव की नितांत आवश्यकता पर बल देती है। इस नीति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से युक्त समग्र और बहुमुखी प्रतिभा वाले चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करना है। इस नीति के महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक 2025 ई. तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे कम-से-कम एक व्यवसाय सीख सकें तथा अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को सभी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में सम्मिलित कर उन्हें कई और व्यवसायों में शामिल कर सकें। क्रियान्वयन की दृष्टि से सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 6 से 8 तक प्रारंभ किया जाने वाला पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम मुख्य रूप से गतिविधि-आधारित शिक्षण-पद्धति पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य पुस्तक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान के बीच के अंतर को कम करना है जो कि अंततः बच्चों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कौशल आवश्यकताओं के विषय में जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें भविष्य के व्यवसाय के विषय में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगा। कृषि, मोटर वाहन, सौंदर्य तथा आरोग्य, आईटी/आईटीईएस, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल, नलसाजी, पर्यटन, आतिथ्य , वेल्डिंग आदि अनेक पाठ्यक्रमों को वृहद रूप में उपलब्ध करा कर युवाओं के कौशल विकास का प्रबंध करना इस नीति का लक्ष्य है। विश्व में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, बिग डाटा, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि अनेक परिकल्पनाएँ हमारे समक्ष हैं जिनके द्वारा भविष्य के रोजगार उपलब्ध होंगे। इन कौशलों का भारतीयों में विकास हो, इसके लिए आकलन और प्रयास हो, ऐसी अपेक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है। इन प्रयासों का परिणाम विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा, रोजगार या आजीविका में जाने पर परिलक्षित होंगे।

भारतीय चिंतन में विद्या के लिए कहा जाता है- ''सा विद्या या विमुक्तये''। अर्थात् विद्या वही जो मुक्त करने वाली हो। भारत केंद्रित यह शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रारंभिक शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार करके विद्यार्थियों की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने को प्रमुखता प्रदान करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए समानता पर आधारित समावेशी उत्तम शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देती है। प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के बाद व्यक्ति स्वावलंबी होने की राह पर अग्रसर होगा।

भारतीय चिंतन में विद्या के लिए कहा जाता है- ''सा विद्या या विमुक्तये''। अर्थात् विद्या वही जो मुक्त करने वाली हो। भारत केंद्रित यह शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रारंभिक शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार करके विद्यार्थियों की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने को प्रमुखता प्रदान करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए समानता पर आधारित समावेशी उत्तम शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देती है। प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के बाद व्यक्ति स्वावलंबी होने की राह पर अग्रसर होगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनी अंतर्निहित भावनाओं के साथ भारत में क्रियान्वित की जाएगी। भारतवर्ष हमेशा से विश्व को राह दिखाने वाला रहा है और आने वाले दशक में यह शिक्षा नीति अपेक्षा करती है कि हम विश्व में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को योग्य बनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएँगे। जिससे पुनः विश्व गुरु बनने का हमारा सपना साकार हो पाएगा। ❑

वोकेशनल अर्थात् व्यावसायिक शिक्षा किसी भी देश की इकॉनमी की पूँजी होती है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति वहाँ के वोकेशनल एजुकेशन पर निर्भर करती है। व्यावसायिक शिक्षा देश की प्रगति का मेरूदण्ड होती है, जिस पर संपूर्ण देश टिका रहता है।

व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियाँ

डॉ. जसपाल सिंह वरवाल
दूरस्थ निदेशालय,
जम्मू विश्वविद्यालय

हमारा भारत संस्कृति की धरोहर कहे जाने वाला देश है, जो विविधता में एकता का प्रतीक कहा जाता है। आज पूरे विश्व में विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की चर्चा हो रही है, आज का भारत सभी क्षेत्रो में प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। नए सपने मन में जगे हैं, नया उजास चारों ओर आगे बढ़ रहा है। सभी लोगों के सपनों की उड़ान के साथ नए भारत की कल्पना हो रही है। हम ने भारत में कई क्षेत्रों में विकास की राह पकड़ ली है। हम भारत के सर्वांगीण विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी नए भारत की हम कल्पना करते हैं तो कई क्षेत्रो में सुधार की, आधुनिकता की, पारदर्शिता की और सांस्कृतिक विकास की ओर कई मुद्दे हैं, जो हमारे नए भारत में साकार होने आवश्यक हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि 'शिक्षा' व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए वक्त के साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाता रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : शिक्षा नीति भी समय की माँग और जरूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने के लिए लाई गई है। शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है।

व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा होती है, जिसके द्वारा किसी खास विषय या क्षेत्र में महारत हासिल की जाती है। यह कौशल प्रशिक्षण की शिक्षा होती है। ये दुनिया हुनरदार लोगों को ही पूछती है। पहले माँ-बाप अपने बच्चों को डाक्टर इंजीनियर बनाना ही पसंद करते थे, क्योंकि केवल इसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सुनिश्चित हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण और कुशलता हमारे करियर रूपी ट्रेन का इंजन है, जिसके बिना हमारी जिन्दगी की गाड़ी चल ही नहीं सकती, इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, स्कील्ड तो होना ही पड़ेगा। यह स्थिति तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है, जब बात गरीबों की आती है। उनके पास इतने पैसे नही होते कि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, इस स्थिति में रोजगार पाने का एकमात्र साधन केवल और केवल व्यावसायिक शिक्षा ही रह जाती है, जो बेहद कम खर्चे में लोगों को स्कील्ड कर रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध होती है।

अब इस क्षेत्र में भी आधुनिकता ने अपने पंख पसार लिए है। बहुत सारी

कंपनियाँ भी प्रशिक्षित लोगों की तलाश में रहती हैं, विभिन्न जॉब वेबसाइटों में कुशल लोगों की रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, जिसमें आनलाइन आवेदन माँगे जाते हैं। कुछ प्रोफेशनल वेबसाइट अब ऑनलाइन कोर्सेज भी कराती हैं। अब आप घर बैठे ही ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुदूर गाँव में बैठे लोगों के लिए यह व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं। हर साल लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं, जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। और जिन कुशल लोगों की माँग है, उनकी संख्या कम है। इस कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा।

मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों के नए भारत में तकनीकी विकास की दर इतनी तेजी से बढ़ेगी कि भारत दूसरे देशों से हर क्षेत्र में मुकाबला कर पायेगा। तकनीकी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकसित होना जरूरी है। नौकरियाँ, पर्यटन, खेल, चिकित्सा, शिक्षा, अर्थव्यवस्था आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए नए उपकरण प्रदान कर तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देकर भारत के तकनीकी विकास की दर तेजी से बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा के लाभ

1. व्यवसाय के लिए तैयार - वोकेशनल अर्थात् व्यावसायिक शिक्षा हमें जॉब के लिए तैयार करता है। यह छात्रों को प्रशिक्षित कर उन्हें ट्रेनिंग और कौशल प्रदान करता है; जोकि अध्यापक, डॉक्टर, इंटीरियर डिजायनिंग, फैशन डिजायनिंग, कम्प्यूटर नेटवर्किंग इत्यादि जैसे क्षेत्रों में बिना प्रशिक्षण कौशल के आप कुछ नहीं कर सकते। यदि इन क्षेत्रों में अपना भविष्य तलाशना है तो बिन ट्रेनिंग के काम नहीं चलने वाला।

2. मितव्ययी शिक्षा - सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के संगठन बहुत ही कम फीस में व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यह उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो किसी कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, या जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं और वो तीन-चार साल पढ़ाई पर नही दे सकते। ऐसे छात्र छमाही या सालाना कोर्स करके रोजी-रोटी कमाने लायक बन सकते हैं।

3. व्यवसाय के अनुकूल - वोकेशनल शिक्षा उपयुक्त ट्रेनिंग देकर रोजगार के नये अवसर प्रदान करता है। यह आज की जरूरत भी है और महत्त्वपूर्ण भी। बड़ी-बड़ी कम्पनियों को भी काबिल और हुनरमंद लोगो की तलाश रहती है। जिनके पास उपयुक्त व्यावसायिक शिक्षा होती है, उनके पास नौकरी की कभी कमी नहीं रहती है। इनकी हर जगह डिमांड बनी रहती है।

4. उन्नत करियर - व्यावसायिक शिक्षा जॉब पाने में हर रास्ता आसान करती है। वो लोग जो पहले से कहीं कार्यरत हैं और खुद को और निखार कर अपना जॉब प्रोफाइल उन्नत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वोकेशनल शिक्षा बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इनकी अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। इच्छुक छात्र बेहद कम समय में ट्रेंड होकर अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, और रोजगार के बेहतर अवसर पा सकते हैं।

5. समय की माँग - आज हर क्षेत्र में नये शोध और अनुसंधान हो रहे हैं। इसको देखते हुए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। समय के साथ आवश्यकताएँ भी बदलती रहती है। पहले लोग परंपरागत खेती-बाड़ी ही करके खुश रहते थे, जितना उगता था, पर्याप्त होता था, जनसंख्या कम थी और लोगों की जरूरते भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, देश की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ लोगों का जीवनस्तर भी समृद्ध हुआ। जीवनस्तर बढ़ा तो लोगों की आवश्यकताएँ भी बढ़ी। अब केवल एक आदमी के कमाने से काम नही चलने वाला। अब कृषि भी काफी उन्नत हो चुकी है। कृषि को बढ़ाने के लिए कई सारे तकनीक आ गये हैं।

व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियाँ -

- देश के युवाओं को नवीन संस्थान उपलब्ध करवाने होंगे जिससे वे स्वयं के सपने साकार कर सकें।
- बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यवसायी प्रदान करने होंगे जो नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सके।
- सस्ती व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाना।
- व्यावसायिक शिक्षा में 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं हस्त प्रशिक्षण को सुनिश्चित किया जाए।
- सभी को आवश्यक रूप से रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद इंटर्नशिप भी करवाई जाए।
- व्यावसायिक शिक्षा को निरंतर मूल्यांकित किया जाना चाहिए ताकि जल्दी नवीन तकनीक को शामिल किया जा सके।
- बीमार संस्थानों को समर्थवान बनाने में सरकारों और एक्सपर्ट्स को साथ काम करना होगा।
- देश के युवाओं को अपनी मातृ भाषा में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवानी होंगी।
- व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की लगातार निगरानी रखनी होगी तभी गुणवत्ता बनी रह पाएगी।
- व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए नए उपकरण प्रदान करने होंगे।

निष्कर्ष

वोकेशनल अर्थात् व्यावसायिक शिक्षा किसी भी देश की इकॉनमी की पूँजी होती है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति वहाँ के वोकेशनल एजुकेशन पर निर्भर करती है। व्यावसायिक शिक्षा देश की प्रगति का मेरूदण्ड होती है, जिस पर संपूर्ण देश टिका रहता है। ❑

व्यावसायिक शिक्षा और सामूहिक उद्यमिता विकास

डॉ. शिवशरण कौशिक
अध्यक्ष एवं सहायक आचार्य,
हिंदी विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
राजगढ़ (अलवर)

आज देश व समाज के आर्थिक नवोत्थान के स्वप्न को साकार करने के लिए संपूर्ण भारत वर्ष के युवाओं के समक्ष उनकी ऊर्जा का समुचित उपयोग करते हुए उनकी उद्यमिता के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था करना ही व्यवसायिक शिक्षा का सही उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यधारा की शिक्षा के साथ रोजगार-संपन्न व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधानों पर पूरा जोर है। आचार्य चाणक्य ने कहा है - ''सुखस्य मूलम धर्मः; धर्मस्य मूलम अर्थः। अर्थात् राष्ट्र-जीवन में समाज के सर्वांगीण विकास का विचार करते समय अर्थ की चिंता करना अपरिहार्य होता जाता है। आज पूरे विश्व के विकास की अवधारणा अर्थ-केंद्रित हो रही है जिसमें समाज-जीवन के विभिन्न घटकों का समावेश करना और उनका विकास किया जाना ही देश के धारणक्षम विकास की आधारशिला है। आज विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ स्थानीय कृषि, उद्योग, व्यापार तथा विभिन्न कला क्षेत्रों की शिक्षा देना और उनमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना व्यावसायिक शिक्षा की पहली प्राथमिकता है।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में युवाओं को मुख्यधारा की सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के समावेश को पुरजोर प्राथमिकता दी गई है और कुछ ऐसे समावेशी पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया है जिनमें औपचारिक शिक्षा तथा उसके समानांतर व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान समाहित है। वर्तमान भारत युवाओं की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में उच्च स्थान पर है। इसी के साथ भारत में ऐसे युवाओं की संख्या भी बहुत अधिक है जो या तो अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे हैं अथवा उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है किंतु वे किसी भी प्रकार के रोजगार के आकांक्षी हैं; इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में युवाओं के उद्यमिता विकास और उनकी क्षमताओं का उपयोग कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है। आज हमारे देश में युवाओं को उद्योग, कृषि, पशुपालन, तकनीक, विधि, सामरिक सेवा, सामुदायिक सेवा, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बढ़ईगिरी, भवन निर्माण, प्रस्तर कला, ताम्र आदि धातु कला, चित्रकारी, रंगाई-छपाई, मधुमक्खी पालन, लेखन-प्रकाशन, भारतीय पेय निर्माण, दुग्ध डेयरी व्यवसाय, कृषि एवं बागवानी, फल-फूल उत्पादक व्यवसाय, खाद्यान्न, तिलहन व दलहन उत्पादन तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से प्लंबरिंग, इलेक्ट्रीशियन, इंटीरियर

डिजाइन आदि क्षेत्रों के साथ नृत्य, संगीत आदि में कौशल विकास आधारित व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। यदि देश का युवा कौशल संपन्न होगा, तो वह आत्मनिर्भर बन सकेगा और अपनी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए देश के सतत विकास में भी सहयोगी बनेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उक्त वर्णित विविध क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों का निर्माण की चर्चा है और बहुविषयक पाठ्यक्रम, बहुभाषी पाठ्यक्रम, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम आदि को व्यावसायिक पूर्तियों के उद्देश्य से मुख्यधारा की शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। यह कौशल विकास की तथा उद्यमिता विकास की अवधारणा युवाओं में श्रम की महत्ता को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही उनमें व्यावसायिक आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित करेगी। शिक्षा के भारतीय व्यावसायिक क्षेत्रों में अध्ययन अध्यापन और शिक्षण-प्रशिक्षण और व्यवसाय की अपार संभावनाएँ हैं। इससे भारतीय शिक्षा पद्धति का एक नया मॉडल तो तैयार होगा ही, साथ ही यह विश्वव्यापी रोजगारपरक शिक्षा-व्यवस्था को मार्गदर्शन देने का भी काम करेगा।

व्यावसायिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में सामूहिक उद्यमिता के विकास का भारत का स्वप्न उसकी युवा पीढ़ी के कौशल पूर्ण और उद्यमिता-संपन्न होने से ही पूर्ण हो सकता है। देश में चल रही पुरानी योजनाओं और शिक्षा नीति में परिवर्तन के साथ एक नई शिक्षा-कार्य-योजना व्यावसायिक शिक्षा के साथ लागू हुई है। नई स्थितियों का निर्माण भी स्वाभाविक ही है; आज पूरे विश्व के शैक्षिक वातावरण में रोजगार और व्यवसाय केंद्रित अवधारणा का विविध रूपों में विश्लेषण और विवेचन हो रहा है। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के सामूहिक व्यावसायिक प्रयत्नों का नया वातावरण बनना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों में सामूहिक उद्यमिता के साथ स्वदेशी विकास केंद्रित और स्वदेशी व्यवसाय केंद्रित शिक्षा नीति स्पष्टता के साथ समूचे देश में लागू हो सके। अन्य विकसित देशों के समान भारत को भी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी नीतियों का निर्माण करना अपरिहार्य हो गया है जिनकी क्रियान्वित से युवाओं के साथ देश की स्थिति को भी मजबूती प्रदान की जा सके। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का सामाजिक तथा आर्थिक विकास एक साथ होगा और आर्थिक विषमता दूर होगी।

आज देश को एक ऐसी समर्थ शिक्षा प्रणाली की प्रबल आवश्यकता है जो देश की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने, नागरिकों में स्वावलंबन के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और जीवन मूल्यों की रक्षा के साथ-साथ रोजगार के समुचित अवसरों का भी प्रबंध कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का प्रावधान किया गया है तथा अनेक नए पाठ्यक्रमों की भी योजना की गई है। हमारे संविधान में भी सरकारों द्वारा सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान किए जाने का प्रावधान है और यह आर्थिक न्याय रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाने पर ही दिया जा सकता है। रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थी को शिक्षित तथा कुशल बनाने का कार्य शिक्षा जगत से ही होता है। अत: हमारे पाठ्यक्रमों का निर्माण ऐसा हो जिन से रोजगार के अनेक अवसरों की विद्यार्थियों को जानकारी भी मिलती रहे और उनको योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध भी हो सकें। यह भी माना जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता, योग्यता तथा क्षमता भिन्न-भिन्न होती हैं तथा उनकी इन सभी विभिन्नताओं के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभिक उद्देश्य है।

वस्तुतः समग्र रूप में भारत के युवाओं का यह विश्वास है कि विद्यार्थी के रूप में वह भारत का भविष्य ही नहीं है, अपितु वर्तमान का जिम्मेदार नागरिक भी है। विद्यार्थी वर्ग सदा ही देश के राष्ट्रीय-समाज का अभिन्न अंग रहा है और वह सामूहिक रूप से राष्ट्रीय हितों को अपना दायित्व समझता रहा है। आज हमारे युवा विद्यार्थी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समुचित और सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। इसलिए कभी राष्ट्रीय विचारधारा के विद्यार्थियों के एक संगठन ने यह नारा दिया था -

''शिक्षा पाकर करें नौकरी,
यह मजबूरी क्यों ?
अपने पैरों खड़े रहें,
हम श्रम से दूरी क्यों ?
हो विपरीत भले ही,
आंधी कदम बढ़ाएंगे
नया इतिहास रचाएंगे,
नया इतिहास रचाएंगे!!''

स्वरोजगार और स्वावलंबन की इसी मान्यता के केंद्र में आज देश के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगात्मक कार्यों की प्रदर्शनी आयोजित होने लगी हैं जिनमें विद्यार्थियों के साथ उद्योगपतियों, प्रतिष्ठित व्यवसाइयों और उदीयमान युवा उद्यमियों के साथ परस्पर इस बात का विचार विमर्श होता है कि युवाओं के रोजगार का प्रबंध कैसे किया जाए ? और उनकी योग्यता तथा क्षमताओं का सदुपयोग कैसे किया जाए? आज विद्यार्थियों में स्वावलंबन के भाव को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है। आज आवश्यकता है अभियांत्रिकी, कृषि, आयुर्विज्ञान तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार की; जिससे भारत के हस्तशिल्प, कला- कौशल, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में भारतीय दृष्टिकोण के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।

युवाओं द्वारा स्वरोजगार की दिशा में किये गए उल्लेखनीय कार्य का उल्लेख यहाँ समीचीन होगा, यह उदाहरण सांगली महाराष्ट्र का है जहाँ ''सहकारिता क्षेत्र के अपने वैचारिक अधिष्ठान के एक प्रमुख कार्यकर्ता श्री माधवराव गोडबोले ने सन 1936 में स्थानीय राष्ट्रवादी विचार के लोगों को साथ लेकर एक नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की थी। लगभग तीन-चार वर्षों में ही बैंक का सुफल सामने आने लगा। तब के कालखंड में नागरिक सहकारी बैंक निम्न एवं मध्यम वर्ग के विकास में प्रत्यक्ष सहायक हुआ करते थे। इस बैंक के माध्यम से भी ऐसा ही वायुमंडल बनने लगा तभी से माधवराम को विश्वास हो गया था कि इसी प्रकार सहकारिता क्षेत्र के कार्यों के माध्यम से हम सामान्य जनों की अर्थ समृद्धि के कार्य संपादित कर सकते हैं। पूरे विश्व के समान ही आज भारत में भी आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के चलते बैंकिंग तथा आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप सहकारी संस्थाओं का क्षेत्र जो अपने दायरे में बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवसाय से भी जुड़ा है, इन गतिविधियों से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह सहकारी समितियाँ बैंकिंग विपणन, भवन निर्माण और उद्योग धंधों के क्षेत्रों में मार्गदर्शन और वित्तीय संरक्षण का प्रयास करती हैं। इसके अतिरिक्त भी कमजोर वर्गों के लिए योजनाएँ भी तैयार कर रही हैं। कुछ जनता सहकारी बैंकों ने निम्न आय वर्ग के लोगों और लघु औद्योगिक इकाइयों के हजारों लोगों को लाभान्वित किया है।''

उल्लेखनीय है कि देशभर में उच्च शिक्षा के केंद्र विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थाओं की कोटि में आते हैं। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के एक्ट संबंधित विधानसभा द्वारा पारित होते हैं। इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय

शैक्षिक मंथन मासिक सम्बन्धी विवरण
घोषणा पत्र फार्म-4 (नियम 8 के अनुसार)

1.	प्रकाशन स्थान	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	मासिक
3.	मुद्रक का नाम (क्या भारत का नागरिक है)	**महेन्द्र कपूर** हाँ भारती भवन, बी-15, न्यू कॉलोनी, जयपुर (राज.)302001
4.	प्रकाशक का नाम (क्या भारत का नागरिक है)	**महेन्द्र कपूर** हाँ भारती भवन, बी-15, न्यू कॉलोनी, जयपुर (राज.)302001
5.	सम्पादक का नाम (क्या भारत का नागरिक है)	**डॉ. शिवशरण कौशिक** हाँ 'कौटीर्या' बी-34, सूर्य नगर तारों की कूट, जयपुर (राज.) 302019

6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र की समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार हों। - **शैक्षिक मंथन संस्थान, जयपुर**

मैं महेन्द्र कपूर एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 1.3.2023

ह0/-
प्रकाशक

अनुदान आयोग आर्थिक सहायता देता है एवं राज्य सरकार ही बजट आवंटित करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग काफी दिनों से कह रहा है कि विश्वविद्यालयों को आय के अपने स्रोत विकसित करने का प्रयास करना चाहिए तथा उसे आयोग के अनुदान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उधर आर्थिक भार वहन करने के कारण राज्य सरकारें भी इन विश्वविद्यालयों पर अपना शिकंजा कसती जा रही हैं और इनकी स्वायत्तता को खंडित कर रही है। यह इस बात को दर्शाता है कि विश्वविद्यालय भी अब रोजगार उपलब्ध कराने में अपने वित्तीय संसाधनों की अपेक्षा युवाओं के स्वावलंबन पर अधिक जोर देने लगे हैं। आज विदेशी कॉरपोरेट शिक्षण संस्थाओं के मुनाफे को ध्यान में रखकर स्थापित संस्थानों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों, जैसे - प्रौद्योगिकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन आदि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को ही पढ़ाने में अधिक रुचि रहेगी; जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में इन वैश्विक-व्यावसायिक विषयों के अतिरिक्त स्थानीय विषयों पर भी पाठ्यक्रमों के अध्ययन-अध्यापन का प्रावधान किया गया है। यह स्पष्ट ही है कि विदेशी विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए इन संस्थानों का संचालन और पाठ्यक्रमों का निर्माण करेंगे, जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय दृष्टिकोण के पाठ्यक्रमों का निर्माण किए जाने पर अधिक जोर दिया गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए कई आयोग और समितियों का गठन किया गया था जिन्होंने अपने गहन विचार विमर्श के पश्चात अध्ययन और शोध के गिरते स्तर को उन्नत करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव भी दिए। लेकिन राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में इन वैश्विक-व्यावसायिक विषयों के अतिरिक्त स्थानीय विषयों पर भी पाठ्यक्रमों के अध्ययन-अध्यापन का प्रावधान किया गया है। यह स्पष्ट ही है कि विदेशी विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए इन संस्थानों का संचालन और पाठ्यक्रमों का निर्माण करेंगे, जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय दृष्टिकोण के पाठ्यक्रमों का निर्माण किए जाने पर अधिक जोर दिया गया है।

आयोग, प्रो. यशपाल जैसे अनुभवी लोगों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाएँ कभी भी क्रियान्वित नहीं हो सकीं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु कुछ वर्षों पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने अपनी 90 पृष्ठों की रिपोर्ट सरकार को दी थी जिसमें अनेक उदात्त सुझाव तत्कालीन सरकार के समक्ष रखे। परंतु सचाई यह है कि इन सब समितियों के उदात्त सुझाव केवल सुझाव ही रहे। हमारे संविधान की भी यह विसंगति है कि उसमें लक्ष्यों को तो परिभाषित कर दिया गया है किंतु उन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले साधनों को परिभाषित नहीं किया गया है। यही वजह है कि हम संवैधानिक प्रावधानों को लागू नहीं कर पाते हैं। यही हाल इन आयोगों और समितियों की रिपोर्टों का रहा। यद्यपि इनका लक्ष्य तो बहुत बड़ा और उदात्त रहा पर 'अब इन्हें प्राप्त कैसे करें' उन साधनों की कोई व्याख्या नहीं की गई। प्रो. यशपाल समिति ने स्पष्ट शब्दों में अनुशंसा की थी कि ''उच्च शिक्षा सरकार तथा लाभ कमाने वाली निजी (आढ़त) एजेंसी के शिकंजे से मुक्त हो''। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को व्यवसाय की ओर धकेलने वाले कुछ दशकों के विपरीत वर्तमान सरकार ने शिक्षा में व्यावसायिक उद्यमिता के प्रवेश का बीड़ा उठाया है, जो यह कहती है कि ''पूरी उच्च शिक्षा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से अलग नहीं रखा जा सकता।'' इसी दृष्टि से शिक्षण और शोध भी संपन्न हों। आगे कहा गया कि ''उच्च शिक्षा रोजगार बाजार के लिए एक सीढ़ी तो है, किंतु शिक्षा सभी प्रकार के भेदभाव को दूर कर सकने की सामर्थ भी रखती हो'' इस प्रकार विश्वविद्यालय मानवतावादी मूल्यों के संरक्षक हों तथा उनमें शिक्षा पाने वाले युवकों को इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक शिक्षा मिल सके कि वे बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप अपने को ढाल सकें। उच्च शिक्षा युवकों में एक वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करे जिससे वह पूरी दुनिया के साथ संवाद करने की स्थिति में हो। अब तक के हमारे सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन किया जाकर उन्हें व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। अब भारतीय उच्च शिक्षा को स्थानीय कारीगरों और किसानों आदि के कार्यों से दूर नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार और भी अनेक बातें कही गई हैं जिनके समाधान हेतु वर्तमान भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में जारी की है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी संस्थानों को भारत में लाने का आग्रह नहीं रखकर, भारतीय शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि कर उन्हें विदेशों में अपनी प्रामाणिकता और गुणवत्ता स्थापित करने के अवसर प्रदान करने वाला बनाये जाने का संकल्प है। ❑

व्यावसायिक शिक्षा मैं हस्तकार्य का मुख्य स्थान है। अतः हम इस कार्य को करके, अपने और अपने परिवार के सम्मान का संहार करना नही चाहते है। हमारे दृष्टिकोण को 'कोठारी कमीशन' ने निम्नलिखित शब्दों मे अंकित किया है - ''दुर्भाग्य से, अभी भी व्यापक रूप मे यह अनुभव किया जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा, निम्न कोटि शिक्षा है।''

व्यावसायिक शिक्षा के विविध संदर्भ

डॉ. लक्ष्मीनारायण बेहेरा
सहायकाचार्य, श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, श्रीविहार, पुरी, ओडिशा

अंग्रेजों के दो सौ वर्ष लम्बे शासनकाल मे भारत के उद्योग, पतन के निम्नस्तर पर थे। उन्होंने अपने देश के उद्योगों को पुष्पित रखने के लिए, हमारे देश में प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के मार्ग में भाँति भाँति की बाधाएँ उपस्थित करके हमारे उद्योगों को क्षयशील एवं मरणोन्मुखी दशा में रखा। स्वतन्त्रता के पश्चात् उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए बहुमुखी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। परन्तु विभिन्न समस्याओं के कारण यह शिक्षा अपनी राह पर डगमगाती हुई ही आगे बढ़ रही है। इस दिशा में आने वाली कुछ गम्भीर चुनौतियों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

हस्तकार्य के प्रति अनुचित दृष्टिकोण

संसार के महान् विचारक, कारलयाल का मत है- ''श्रम ही जीवन है। हमारे युग का सच्चा महाकाव्य-उपकरण और मनुष्य है।''

"Labour is life.The true epic of our times is tools and the man." - Carlye Quoted from The New Dictionary of Though's

आधुनिक युग में प्रगति का रहस्य एवं सूत्र मन्त्र-श्रम है। इसी सूत्र मन्त्र को अपना दिशा-निर्देशक बनाकर रूस, जापान, अमरीका आदि देशो ने अभूतपूर्व उन्नति की है। इसके विपरीत, हमारे देश में सुदूर अतीत से ही शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा गया है। यह भावना ''हमारी नस-नस मैं घुसी हुई है और हमारे आदर्श की अनमोल प्रतिभा बनी हुई है।'' यही कारण है कि आज भी शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं और हस्तकार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने से निम्नस्तर समझते हैं। ये भले ही कौशलों एवं हस्तकलाओं में प्रवीण होने के कारण असाधारण हों, पर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा में हस्तकार्य का मुख्य स्थान है। अतः हम इस कार्य को करके, अपने और अपने परिवार के सम्मान का संहार करना नहीं चाहते हैं। हमारे दृष्टिकोण को 'कोठारी कमीशन' ने निम्नलिखित शब्दों मे अंकित किया है - ''दुर्भाग्य से, अभी भी व्यापक रूप मे यह अनुभव किया जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा, निम्न कोटि की शिक्षा है।''

दोषपूर्ण पाठ्यक्रम

हमारी प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों मे दो मुख्य दोष है - संकीर्णता एवं समरूपता। उनमें व्यापकता और विविधता, बहुचयनता और बहु-उद्देश्यता का पूर्ण अभाव है। उनका निर्माण छात्रों की विभिन्न रुचियों एवं

उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। अत: वे छात्रों और उद्योग-दोनों के लिए अहितकर, अनुपयोगी एवं अनुपयुक्त है। इसकी पुष्टि में तीन प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

पहला, पाठ्यक्रम् में निर्धारित समस्त रुचियों विषयों का अध्ययन सब छात्रों के लिए अनिवार्य होता है। अत: उनको अपनी रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसका परिणाम होता है - परीक्षा में असफलता, जो अपव्यय एवं अवरोधन को जन्म देती है।

दूसरा, समान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के कारण समान शैक्षिक योग्यताओं वाले इतने व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं कि उनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं। इसका परिणाम होता है - बेरोजगारी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं में इस बेरोजगारी के कारण ही छात्रों की संख्या कम हो गई थी।

तीसरा, समय की गति के साथ देश की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। परिणामत: देश के उद्योगों का मार्ग बदल रहा है। समरूप पाठ्यक्रम इन बदलती हुई माँगों की पूर्ति करने में विफल होते हैं।

शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम

2 सितम्बर 1956 के राज्य-शिक्षामन्त्रियों के सम्मेलन में भाषण देते हुए, श्री नेहरू ने कहा था - ''बिल्कुल स्पष्ट है कि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा।'' उस समय से आज तक प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है और हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने इसमें परिवर्तन करने का कभी कोई विचार प्रकट नहीं किया है। जब ये छात्र इन संस्थाओं में प्रवेश करते हैं, तब ये अपने को बिल्कुल नई दुनियाँ में पाते हैं। उन्होंने वर्षों से अपनी मातृभाषा में सुना और समझा, पढ़ा और लिखा है। पर अब उनको अंग्रेजी में सुनने और समझने, पढ़ने लिखने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके सभी दुष्परिणाम स्वयं विदित है। न तो वे कक्षा में शिक्षकों के व्याख्यानों को समझ पाते हैं और न पुस्तकों में लिखी हुई बातों को।

व्यावहारिक प्रशिक्षण की उपेक्षा

हमारे देश की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं के विरुद्ध एक आम शिकायत यह है कि उनमें जितना बल सैद्धान्तिक शिक्षा पर दिया जाता है, उनका दशांश भी व्यावहारिक प्रशिक्षण पर नहीं दिया जाता है। इस शिकायत की नागफांस से बचने के लिए शिक्षा संस्थाएँ दो तर्क प्रस्तुत करती हैं। पहला, उनके वर्कशॉपों और प्रयोगशालाओं में उपकरणों का अभाव है और जो उपकरण है भी, वे इतने पुराने हो चुके हैं कि आधुनिक उद्योगों की दृष्टि से उनकी उपादेयता नष्ट हो चुकी है। दूसरा, उनके क्षेत्रों में स्थित फैक्टरियाँ और औद्योगिक केन्द्र उनके छात्रों को अपने यहाँ व्यावहारिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं।

शिक्षकों का अभाव

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की एक दु:साध्य समस्या-शिक्षकों का अभाव और इस अभाव की अविराम अभिवृद्धि हैं। दोनों स्तरों पर शिक्षकों के अभाव के दो आधारभूत कारण हैं - उद्योगों द्वारा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की माँग और प्राविधिक संस्थाओं में इन व्यक्तियों को कार्य करने की अनिच्छा। प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त योग्य व्यक्तियों की सभी उद्योगों में माँग रहती है। इसके विपरीत, शिक्षा-संस्थाओं में उनको मिलता है - अल्प वेतन और जीवन एवं कार्य करने की असुविधापूर्ण दशाएँ। आज की व्यावसायिक शिक्षा में यह भी एक गम्भीर चुनौती है।

अध्ययन के उपरान्त शिक्षा का अभाव

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। परन्तु जो छात्र प्राविधिक या व्यावसायिक संस्थाओं में अपना अध्ययन करने के उपरान्त किसी उद्योग या व्यावसाय में प्रवेश करते हैं, उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने अध्ययन काल में जिस ज्ञान का अर्जन करते हैं, वह समय की गति के साथ-साथ सीमित होता जाता है। इसका उनकी दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसकी अवनति आरम्भ हो जाती है।

इसके अतिरिक्त हमें व्यावसायिक शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न चुनौतिओं का सामना करना पड़ता है। व्यवसायिक शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए समस्याओं का समाधान करना अनिवार्य है। ❑

Vocational Education and Traditional Education

Dr. T.S. Girishkumar
Professor of
Philosophy (Rtd.)
MSU Baroda
(Gujarat)

The present world is constantly, evolving into amazing directions. Gone are the days of military invasions, conquests and dominations, the world order has changed from erstwhile barbaric, brutal ways. Those who fail to get updated and cop up with the changing times are bound to lag and indeed, suffer.

Ways of conquests had become business oriented; corporates keep having their ways apart from says, and they had gone to establish their kind of domination in the world. And it is not only natural, but also mandatory for us to update our education system also in synchronisation with the changing times, and the requirements of changing times, lest, our generations shall fall behind the so-called race with the time.

Traditional education

We know that traditional education system in Bharat is aimed at man making. Indeed, that ought to be the case. Maharishi Gautama said that knowledge must have the property of 'affectivity', that is, knowledge should be affecting the knower. Let us see it this way: first what comes to us is only information regarding various things or aspects, and this information has to 'become' knowledge to us. For information to turn into knowledge, it has to go through a process, a process of refining the knower. This meens, that, the information that one finds has to refine him, refining in such a manner that impurities are discarded. Sputikarana ought to be the expression in Sanskrit. It is only when information refines the knower into a refined one, a Sanskrita, a Sanskari, that information can become knowledge to the knower.

Bharatiya education had ever been with this ideal, and it is in this manner that original Bharatiya education was carried out in our land, before foreign influences that did their best to destroy Bharatiya Sanskriti and

the Vedopanishadic knowledge tradition. Obviously, there were damages and with British colonialism and McCaulian education, Bharat also got the British pattern of education system imposed upon us. Of course, this had some advantages, but it also had serious disadvantages. With all these, Bharatiya education continued to be in the man making pattern, simply because of the strong presence of Bharatiya Sanskriti, which is based on the Vedopanishadic knowledge tradition.

Truly, if education cannot make a proper human out of a man, then it becomes without purpose. There is no point in filling humans with many information which makes no difference to him, or which one Fails to digest. Thus on a final analysis, education ought to be man making, information should become knowledge through refining the knower into a better human being, and obviously, a Sanskari, a good Bharatiya.

On the surface level, vocational education shall be both skill implanting and skill developing. This should also be training in professionalism, which is deeper skill developing in another sense. A living example is the Indian Air Force itself. They always say that the Air Force is professional Force, because all are professionals in the Air Force. Each one is taught and trained in a profession or trade to create an effective team that controls the skies and makes the aircraft fly.

Corporate world

As mentioned earlier, the present world is more of a corporate one. Perhaps no one can stay away from the corporate culture or ways of existence. Here, competition become the race against time, competing humans has to bring out their best to outwit or out win other competitor. Hard work and struggle go without saying.

Corporate world only looks at how productive one is, not simply how good one is – simply because it is their existence. One has to be both productive to the companies and good at the same time, where goodness is not always intrinsic goodness. They call it as being 'practical' which really can keep changing its meaning from context to context. They will simply make distinctions between ideal and practical too soon without really caring for the merit, but that shall be the case. Speed – time – quick results – visible results – becomes the goals to go after. Here it becomes natural and obvious that the education system should be changing from the old to the new, the new here shall

mean vocational education broadly.

Vocational education

On the surface level, vocational education shall be both skill implanting and skill developing. This should also be training in professionalism, which is deeper skill developing in another sense. A living example is the Indian Air Force itself. They always say that the Air Force is professional Force, because all are professionals in the Air Force. Each one is taught and trained in a profession or trade to create an effective team that controls the skies and makes the aircraft fly.

Vocational education should be akin to this. Everyone should be taught a trade – a profession - depending on his potentials and abilities. The Air Force does this through many tests and examinations before selecting one and allotting him with a profession or trade. In civil society, one can choose his own profession depending on his abilities and aptitude etc., with the help of teachers etc., where need.

This should be resulting in appropriate professionalism and makes it easy for one to find places of work where his abilities are needed by corporates etc. it becomes easy for both parties, for the one who acquires skills according to his abilities and requirements and also for those who are wanting to make use of such abilities to productivity. This practically results in functional and practical co-existence. So, it becomes clear that vocational education as well as professional education must be given priority

and importance.

But just professional education alone can have its shortcomings as well. Rhetorically, borrowing the expression from Marx, it shall be like the soul of soulless conditions, or flowers without fragrance etc. on the one hand, and on the other hand, this could create only monsters of intellect. Frankenstein is an imagination from the west, but Frankenstein is only a monster. We really do not want intellectual monsters in our society. We really do not want the Marxian ideas of 'modes of production' in our society which dehumanises societies and destroys social institutions including families and human relations. There should be other options.

Ideal education

Ideal education ought to be a blend of traditional Bharatiya education and vocational education. Traditional education ought to be the substructure and vocational education of different professions should be the super structure. The substructure shall remain the same for all, but on the substructure, super structures shall vary and remain dynamic in manifold manner.

Whatever may be the changing times, whatever may be the changing requirements of times, we should keep remembering that we are Bharatiyas because of Bharatiya Sanskriti, Bharatiya Sanskriti is an external manifestation from Bharatiya knowledge tradition which is the Vedopanishadic knowledge tradition, without which we shall be simply nothing.

The Rg Veda say, "Anobhadrakritavaoy-anthuvishwatha". We are extremely flexible, adaptable and dynamic, we can accept anything which is worthwhile, but only as superstructures. Our substructure shall ever remain the Vedopanishadic knowledge tradition and that is our confidence in welcoming anything worthwhile, no matter from where, and no matter by whom. ❑

Empowering Youth Through Vocational Education

Darshan Bharti
Teacher Educator,
District Poonch
J&K (UT)

Vocational education is an important part of India's education system. It is an education that prepares students for a specific job or career. Vocational education provides practical skills and training to students, enabling them to succeed in their chosen career paths. In this article, we will discuss vocational education and teachers in India, in context with different National Educational Policies.

National Educational Policy 1968

The National Educational Policy (NEP) of 1968 highlighted the need for vocational education to provide opportunities for young people to develop the necessary skills and knowledge for employment in various sectors. The policy recognized the importance of vocational education in reducing unemployment and promoting economic growth.

Under this policy, vocational education was introduced in secondary schools, polytechnics, and colleges of technology. The aim was to provide students with a wide range of skills and knowledge to prepare them for the workforce. Vocational education was offered in various fields such as agriculture, engineering, commerce, and health care.

The policy also recognized the importance of teachers in vocational education. It highlighted the need for trained teachers who can teach the practical skills required for vocational education. The policy emphasized the need for teachers to be trained in new teaching methods and technologies to meet the changing needs of the workforce.

National Policy on Education 1986

The National Policy on Education (NPE) of 1986 aimed

to provide access to education for all and to promote equality and social justice. The policy recognized the importance of vocational education in providing employment opportunities for young people.

Under this policy, vocational education was integrated into the mainstream education system. The policy aimed to provide vocational education to all students, irrespective of their academic background. The aim was to provide opportunities for students to develop the necessary skills and knowledge to succeed in their chosen career paths.

The policy also recognized the importance of teachers in vocational education. It highlighted the need for trained and qualified teachers who can teach the practical skills required for vocational education. The policy aimed to provide teachers with the necessary training and support to deliver high-quality vocational education.

National Policy on Education 2020

The National Policy on Education (NPE) of 2020 aimed to transform the Indian education system and to prepare students for the challenges of the 21st century. The policy recognized the importance of vocational education in preparing students for the workforce.

Under this policy, vocational education was given equal importance as academic education. The policy aimed to provide vocational education to all students from the secondary level onwards. The policy also recognized the importance of integrating vocational education with academic education to provide students with a wide range of skills and knowledge.

Education is a centrally learner-driven process and it has to be because education aims to allow an individual to gradually reach perfection in all four spheres – physical, psychical, social, and spiritual. Hence in the neohumanist paradigm, P R Sarkar highlights the following crucial issues related to the students which need proper attention while framing policies related to education – Firstly, he holds it is improper to extort anything from students through undue pressure and intimidation. Intimidation appears to work to some extent, but it does not yield lasting results.

The NEP-2020 highlighted the need for trained and qualified teachers in vocational education. It recognized the importance of teachers in providing high-quality vocational education. The policy aimed to provide teachers with the necessary training and support to deliver high-quality vocational education.

Vocational education provides practical skills and training to students, enabling them to succeed in their chosen career paths. In India, there are a wide range of vocational courses available for students to choose from. These courses are designed to provide students with the necessary skills and knowledge required to succeed in various sectors. Some of the popular vocational courses available in India are:

Automotive Technology

This course is designed for

students who are interested in the automotive industry. It provides training in automobile repair, maintenance and diagnostics.

Computer Applications: This course is designed for students who are interested in the field of information technology. It provides training in computer programming, web development, database management and networking.

Beauty and Wellness: This course is designed for students who are interested in the beauty and wellness industry. It provides training in beauty treatments, hair styling, nail art and spa therapies.

Agriculture

This course is designed for students who are interested in the agricultural sector. It provides training in crop production, animal husbandry, agricultural marketing and management.

Healthcare

This course is designed for students who are interested in the healthcare sector. It provides training in nursing, medical transcription, medical lab technology and hospital management.

Fashion Designing

This course is designed for students who are interested in the fashion industry. It provides training in fashion design, textile design, garment manufacturing and fashion merchandising.

Hospitality and Tourism

This course is designed for students who are interested in the hospitality and tourism industry. It provides training in hotel management, event management, travel and tourism.

These are just a few examples of the wide range of vocational courses available in India. Students can choose from a variety of courses based on their interests and career aspirations. Vocational education provides a practical approach to learning and helps students develop the skills and knowledge needed to succeed in their chosen careers.

Challenges faced by vocational education in India:"Despite the efforts made by the National Educational Policies, vocational education in India faces several challenges. One of the main challenges is the lack of awareness about vocational education. Many students and parents view vocational education as a second choice and prefer academic education.

Another challenge faced by vocational education in India is the lack of infrastructure and resources. Many vocational education institutions lack proper infrastructure and resources, which hampers the quality of education.

The lack of trained and qualified teachers is another challenge faced by vocational education in India. Many vocational education institutions face a shortage of teachers who are trained in the practical skills required for vocational education.

Conclusion

In conclusion, vocational education is an important aspect of the Indian education system. It plays a significant role in preparing students for the workforce and reducing unemployment. The National Educational Policies have recognized the importance of vocational education and the role of teachers in delivering high-quality vocational education. Vocational education is an essential part of the education system in India. It provides students with practical skills and knowledge that they can use to build a career and contribute to the economy. ❑

Professional Education and National Education Policy 2020

Prof. Suneel Kumar

Professor,
Department of Commerce,
Shaheed Bhagat Singh College,
(University of Delhi)

Education of an individual is not just about academic curriculum but also about putting theory into practice, inculcating ethics and the significance of serving a public purpose in their professional careers.It is essential that critical and multidisciplinary analysis, communication, argument, knowledge, and creative problem-solving is at the core of this endeavour. In order to achieve this objective, professional education should not be confined to the confines of a single area of expertise. Professional education and the need to revitalize and promote professional courses in the agricultural, legal, medical, and technological domains are discussed in the National Education Policy (NEP) 2020 (MHRD, 2020; Yenugu, 2022). Professional training is an important part of the curriculum for higher education. Institutions in agriculture, law, health sciences, technical education, and other fields should all try to become multifunctional (UGC, 2020). The following areas of professional education are included in the preview of the NEP 2020:

NEP-2020 has changed the way education works in the healthcare field in a meaningful way. The NEP has done an excellent job designing the new course duration, structure, and design of academic programs, which will now be of significant value to learners (Gupta, 2020). Today, students will be evaluated more consistently and regularly based on well-defined criteria that are largely necessary for employment in primary care and secondary hospitals. Because individuals engage in

pluralistic choices concerning healthcare our national healthcare. Education system must become more integrated. This means all homeopathic, medical education students must be familiar with Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy (AYUSH) and its associated practices(MHRD, 2020; Pradeep, 2021). One must have a fundamental understanding of the antithesis. In addition, there will be an increased focus on preventative medical care and community medicine in every type of medical education.

It is planned to bring back agricultural education along with related academic subjects. While agricultural universities make up around 9% of all institutions in the country, less than 1% of all students enrolled in higher education are studying agriculture and related subjects (Chandrakanth, 2022). In order to increase agricultural productivity, it is necessary to improve the capacity as well as the quality of agriculture and the disciplines that are closely related to it. This can be accomplished by increasing the number of graduates and professionals with better skills, conducting research activities, and conducting market-based renewal linked to technology and methods. A significant increase will be made in the number of programs integrated with general education to facilitate the formation of professionals in the agricultural and veterinary sciences. Education programs will focus on creating professionals who can comprehend and use local contacts, ancient traditions, and innovative technologies while also being aware of crucial issues such as reduced soil productive output, global warming, and food self-reliance for our rising population(Pradeep, 2021). This shift in the design of agricultural education will take place over the next few years. Institutions providing agricultural education are obligated to benefit the communities in which they are located directly; one strategy could be establishing agricultural technology parks to encourage the life cycle and propagation of new technology and promote sustainable agricultural practices.

The NEP also encourages a move away from traditional teaching methods that emphasize learning facts and towards a more well-rounded approach to education. In addition to the subject of study, it develops an innovative and diverse curriculum that places equal emphasis on various other topics, such as the humanities, sports, fitness, languages, culture, and the arts, among others. So, it seems likely that the National Education Policy will help change India's education system so that it can better meet the country's needs in the years to come.

The National Education Policy 2020 (NEP 2020) has also emphasized making Indian legal education competitive internationally. The primary objective of the NEP, which is part of the legal education system in India, is to incorporate existing best practices and emerging technology to improve access to justice and shorten the time it takes to provide it(Bose, 2021). The NEP curriculum for legal studies represents the social and economic settings, the history of legal thought, concepts of equity, the practice of adjudication, and other relevant

topics in an evidence-based approach. The provision of legal education by state institutions should involve offering a bilingual education to aspiring attorneys and judges, with instruction in both English and the dialect of the state where the institution is located.

When we talk about technical education, we are referring to the degree and diploma programs that are offered in subjects like engineering, future technologies, management, architectural style, city planning, pharmaceutics, hospitality management, catering technology, and other areas that are essential for the growth and development of India as a whole (NEP 2020). To keep innovation and research going in these fields, there will not only be a big need for skilled workers but the business world and higher education institutions will also need to work closely together. There will likely be less of a gap between technical education and other fields due to technology's influence on human endeavours. Also, there will be a renewed focus on ways to engage with other fields of study, and technical education will be given in facilities and programs that bring together people from different fields of study. Professionals in cutting-edge fields such as artificial intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, machine learning, genetic research, microbiology, nanomaterial, neurology, healthcare, the environment, and green buildings will also be trained. It will boost youth employment in graduate education.

NEP 2020 tries to meet the need to educate the next generation of experts in many fields, from agriculture to artificial intelligence. India must get itself prepared for what lies ahead. Moreover, NEP 2020 opens the path for many young students with big dreams to get the training they need to achieve their goals. Implementing it effective manner will be essential to ensuring its success. The NEP also encourages a move away from traditional teaching methods that emphasize learning facts and towards a more well-rounded approach to education. In addition to the subject of study, it develops an innovative and diverse curriculum that places equal emphasis on various other topics, such as the humanities, sports, fitness, languages, culture, and the arts, among others. So, it seems likely that the National Education Policy will help change India's education system so that it can better meet the country's needs in the years to come.❑

जी-20 अध्यक्षता का वैश्विक दृष्टिकोण

डॉ. हरनाम सिंह
सहायक आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की संकल्पना से ओत प्रोत भारत ने जी-20 के अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। वैश्विक मंगल का भारतीय मार्ग सशक्त, सक्षम, समर्थ और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। वसुधैव कुटुंबकम् की संकल्पना वाले भारत के लिए यह जिम्मेदारी अपने प्रति दुनिया के बढ़ते विश्वास के रूप में देख रहा है। भारत की वर्तमान सफलताओं का आकलन, तो भविष्य को लेकर आशा प्रकट की जा रही है। दो सौ से अधिक स्थानों पर जनभागीदारी वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो रहे हैं। जी-20 का अध्यक्ष बनने से विश्व के अल्पविकसित और विकासशील देश आशा भरी नजरों से भी देख रहे हैं। भारत ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिनसे संपूर्ण विश्व की सुख-शांति-समृधि सुनिश्चित हो। विश्वभर के देशों को यह जिज्ञासा भी है कि जी-20 की अध्यक्षता कर रहा भारत वैश्विक समस्याओं के समाधान में कैसे अपना नेतृत्व देगा? किस तरह से अपनी परंपरा, संस्कृति, विरासत और महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखेगा ? क्या भारत वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को अत्यधिक सकारात्मक और सशक्त रूप से प्रस्तुत कर वैश्विक जिज्ञासा का समुचित समाधान और यहाँ के पर्यटन तथा अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर लाभ ले सकेगा? वैश्विक जिज्ञासा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में भारत तेजी से उभरा है। विगत वर्षों में भारत के पास कई महत्त्वपूर्ण मंचों का नेतृत्व करने का अवसर आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और शंघाई सहयोग संगठन के बाद एक दिसंबर 2022 से जी-20 का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक अवसर भारत को मिला है। जी-20 की अध्यक्षता दर्शाता है कि वसुधैव कुटुंबकम् की भावना से ओत प्रोत भारत की साख और धाक दोनों विश्व में बढ़ रही है। जी-20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85 प्रतिशत जीडीपी और 75 प्रतिशत व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। जी-20 समूह में विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या समाहित है। भारत एक तरफ विकसित देशों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है। भारत का सदैव प्रयास रहा है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो। बल्कि वन वर्ड

भारत पूरे विश्व को एक समान उद्देश्य के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है।

जी-20 में भारत का मंत्र है 'एक पृथ्वी एक परिवार-एक विश्व'। भारत के यही विचार, संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत के लिए जी-20 समूह के समक्ष अपनी 'अतिथि देवो भव' की परंपरा के दर्शन करवाने का भी बड़ा अवसर है। जी-20 से जुड़े दिल्ली के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएँ, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपना सौंदर्य और अपनी विशिष्टता है। भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण यहाँ के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अवसर लेकर आया है।

भारत का स्वस्थ विश्व-विजन

जी-20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठकों में भारत 'सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुख भागभवेत' मंत्र के साथ एक वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के प्रति अपने संकल्प विजन को रखा है। जी-20 का नीति-वाक्य भी यही है 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' जो 'वसुधैव कुटुंबकम्' की अवधारणा से निकला है। कोविड-19 महामारी ने सभी देशों के स्वास्थ्य ढाँचे को झकझोर दिया है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता के मूल उद्देश्य को 'उपचार, सद्भाव और आशा' के रूप में रखकर वैश्वीकरण को और अधिक मानव-केंद्रित करने का विजन रखा है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता है। भारत वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन ढाँचे को मजबूत करने के साथ ही, आपदा रोधी तौर-तरीकों को समाहित कर रहा है। भविष्य की ऐसी चुनौतियों को देखते हुए फार्मास्युटिकल क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण टीकों, चिकित्सा और निदान तक सबकी समान पहुँच बना रहा है। भारतीय जेनरिक दवाइयों की सम्पूर्ण विश्व में महत्त्वपूर्ण

पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास चुनौतियों से संबंधित समाधान है। भारत डिजिटल तकनीक में भी एक बड़ी शक्ति बनने के साथ विश्व में समक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है और अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा शीघ्र हो इसके लिए नीति-नियंत्ताओं को अपने दायित्व का पालन करते समय सचेत रहना होगा। भारत का कद और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे इसके लिए जनता को भी अपने हिस्से की भूमिका भी निभानी होगी। जी-20 की अध्यक्षता से भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त-समृद्ध आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

स्थान है। वित्त वर्ष 2022 में भारत ने 200 देशों को 24.47 बिलियन डॉलर के फार्मा उत्पादों की आपूर्ति की है। सम्पूर्ण विश्व ने भी जीवन रक्षक टीकों की असमानता को दूर करने में भारत की भूमिका को सराहा है। 'वैक्सीन मैत्री' के द्वारा भारत ने सबसे कठिन समय में 100 से अधिक देशों को कोविड वैक्सीन दी थी। भारत कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों को सस्ती दवाएँ और एंटी-टीबी जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। भारत की कोशिश है कि इनके लिए क्लिनिकल टेस्ट, अनुसंधान, विकास सहायता और किफायती चिकित्सा उपायों के लिए एक अनुकूल ढाँचा तैयार हो। जी-20 सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से भारत एक ऐसा ईकोसिस्टम बना रहा है जिससे निम्न-मध्यम आय वाले देशों को एक समान स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का मंच मिले। भारत को जी-20 की अध्यक्षता ने एक 'स्वस्थ विश्व' के स्वस्थ विजन को प्रस्तुत करने का भी मंच प्रदान किया है।

जी 20 से वैश्विक मंगल

'एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य' की संकल्पना से नया भारत वैश्विक मंगल का मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। नया मार्ग जो सशक्त, सक्षम, समर्थ और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। जी-20 की अध्यक्षता भारत के प्रति दुनिया के विश्वास का प्रतीक भी है। 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना के साथ जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने विश्व की सुख-शांति-समृधि के लिए काम करना शुरू भी कर दिया है। भारत की वर्तमान सफलताओं का आकलन, तो भविष्य को लेकर आशा प्रकट की जा रही है। ऐसे में हम देशवासियों की यह जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएँ। जब भारत जी-20 की अध्यक्षता

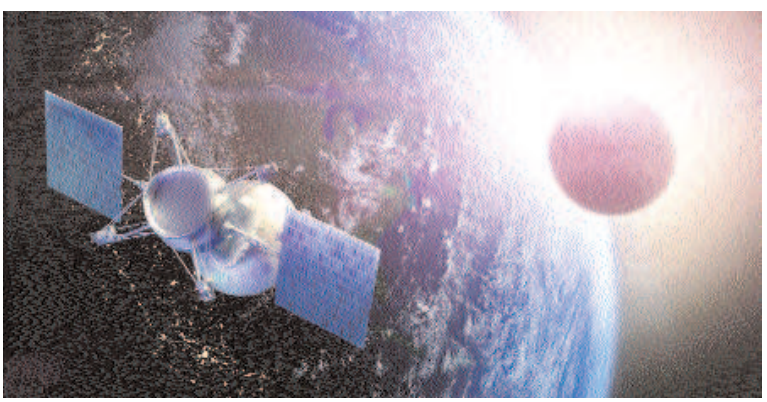

कर रहा है तो यह आयोजन हमारे लिए भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। इसलिए 200 से अधिक स्थानों पर जनभागीदारी वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। केंद्र सरकार सामान्य जन को प्रेरित कर रही है कि विश्व मंगल के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इस अवसर पर कैसे अंतरराष्ट्रीय विश्व की समस्याओं का समाधान भारत अपने नेतृत्व से देगा और साथ ही किस तरह से अपनी परंपरा, संस्कृति, विरासत और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखेगा इसकी तैयारी भी है।

जी-20 आर्थिक सहयोग का मंच

जी-20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो सभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को वैश्विक रूप देने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी-20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की एक मंच के रूप में हुई थी। वर्ष 2007 और 2009 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद शासन प्रमुख के स्तर तक का दर्जा देते हुए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नाम दिया गया था। जी-20 ने शुरुआत में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया था। बाद में इसका विस्तार हुआ और इसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार का विरोध भी जुड़ गया है।

जी-20 सदस्य देश

जी-20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा अतिथि के तौर पर कई अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। जी-20 में भारत, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, तुर्की और यूरोपीय संघ शामिल है जो विश्व के प्रमुख सशक्त देश हैं। भारत ने अतिथि देश के रूप में स्पेन, बांग्लादेश, मिश्र, मारीशस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, नाइजीरिया और ओमान को आमंत्रित किया है। जी-20 राष्ट्राध्यक्षों का 18वाँ शिखर सम्मलेन 09-10 सितम्बर 2023 को नई दिल्ली में होगा। इसमें सम्बन्धित मंत्रिस्तरीय बैठक एवं कार्यसमूहों की बैठकों के दौरान जिन प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई और सहमति बनी उसके प्रति प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति की जायेगी।

जी-20 की कार्यविधि

जी-20 अध्यक्ष एक वर्ष के लिए इस संगठन के एजेंडे का संचालन और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। जी-20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं- वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। इन दो ट्रैक के भीतर अलग-अलग विषयों के कार्य समूह होते हैं जिनमें संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आमंत्रित या अतिथि देश और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल होते हैं। शेरपा वर्ष भर वार्ताओं की देखरेख करते हैं। साथ ही शिखर सम्मेलन के एजेंडे के विषय पर चर्चा करते हैं और जी-20 के खास खास कामों में समन्वय करते हैं। इसके अलावा सहभागी समूह होते हैं। यह समूह जी-20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, थिंक टैंक, महिलाओं, युवाओं, व्यवसाय और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। जी-20 समूह के पास स्थाई सचिवालय नहीं है। अध्यक्ष का साथ पिछले और आने वाले अध्यक्ष देते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान इस ट्राईका में तीनों विकासशील देश क्रमश: इंडोनेशिया भारत और ब्राजील शामिल है।

शेरपा ट्रैक

शेरपा शब्द नेपाली शेरपा से लिया गया है। शेरपा लोग हिमालय में पर्वतारोहियों के लिए बतौर गाइड काम करते हैं। प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिए शेरपा ट्रैक के माध्यम से 13 कार्य समूह और 2 इनीशिएटिव भारत की अध्यक्षता में मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम में जी-20 की निर्णय लेने की प्रक्रिया के भाग के रूप में, कार्यकारी समूहों में विशेषज्ञ और

संबंधित मंत्रालय शामिल होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक अनेक मुद्दों के गहन विश्लेषण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसमें कृषि, भ्रष्टाचार रोकना, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम कम करना, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण-जलवायु स्थिरता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश, जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस बार भारत के जी-20 शेरपा अमिताभकांत हैं। विभिन्न कार्य समूह के माध्यम से शेरपा अपने देश के हितों के पक्ष में माहौल बनाते हैं। हालांकि जी-20 शेरपा का पद प्रभावशाली है, लेकिन उनके पास समझौते का अधिकार नहीं होता। जी-20 सम्मिट में हर सदस्य देश से एक ही शेरपा शामिल हो सकता है, जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। इस पद पर देश का राजनयिक, राजनीतिक अनुभव रखने वाला नेता या वरिष्ठ सरकारी अधिकारी में से कोई भी नियुक्त हो सकता है।

वित्तीय ट्रैक

जी-20 वित्त ट्रैक, वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों, केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों और विभिन्न कार्य समूह की बैठकों के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। वित्त ट्रैक द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे हैं : वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और वैश्विक आर्थिक जोखिमों की निगरानी, अधिक और लचीली वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए सुधार। जी-20 फास्ट ट्रैक में अंतरराष्ट्रीय कराधान, गुणवत्ता परक अवसंरचना का वित्तपोषण, दीर्घकालिक वित्तीयन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, भावी स्वास्थ्य, आपात स्थितियों के लिए वित्तपोषण, महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया में निवेश।

श्रेयस्कर भारत का संकेत

जी-20 की अध्यक्षता से अग्रणी राष्ट्रों का नेतृत्व कर भारत विकसित होने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ से भारत के सशक्त होने एवं विश्व स्वीकार्यता का मार्ग प्रसस्त हो रहा है। भारत ने विश्व को शांति के मार्ग पर अग्रसर करने के अपने संकल्प को दोहराया है। सम्पूर्ण विश्व को सुखी होने का मार्ग दिखाते हुए भारत स्वयं भी उसपर अग्रसर है। पृथ्वी के सभी प्राणी सुखी हों, यह कामना वह व्यक्ति एवं वह राष्ट्र कर सकता है, जो सारी वसुधा को अपना परिवार समझता है। जो उदार, शांतिप्रिय एवं अहिंसक, अपने पराये की संकीर्ण सीमा को लांघकर प्राणीमात्र के सुख में सुखी और दु:ख में दु:खी होता है। यही उदात्त विचारधारा भारतीय संस्कृति और जीवन-पद्धति की विशेषता है। इसी विचारधारा से वसुधैव कुटुबंकम् एवं सर्वे भवन्तु सुखीन के उद्घोष हुए हैं। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का नारा भारत के संस्कारों एवं संस्कृति से विश्व कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करेगा। नये प्रतीक चिह्न के कमल के पुष्प पर विराजित पृथ्वी एवं कमल की सात पंखुड़ियों के माध्यम से सातों महाद्वीपों की एकजुटता और सौहार्द से समृद्धि एवं प्रगति का संदेश मिल रहा है। भारत की छवि लगातार बदलती जा रही है, भारत को दुनिया की महाशक्तियाँ भी स्थान देने लगी, उससे मार्गदर्शन लेकर अपनी नीतियों को बल देने लगी है। जी-20 की अध्यक्षता भारत को करने का अवसर एक नये, शुभ एवं श्रेयस्कर भारत का संकेत है।

जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिए अवसर

भारत दुनिया की एक सशक्त आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए उसने दुनिया की पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जगह बना ली है। अब भारत सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। 20-जी शिखर सम्मेलन की स्वागत भूमि बनकर भारत अपने सशक्त एवं विकसित होने के गौरव को नये आयाम देगा। अनुमान है कि 2029 तक वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं 2027 तक

भारत के जर्मनी और 2029 तक जापान से आगे निकल जाने का अनुमान है। भारत खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, वाणिज्य कौशल की पहचान और आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण के लिये नयी भूमि को तैयार कर रहा है। भारत उन देशों में है जो बहुत तेज गति से इलैक्ट्रिक वाहनों को अपना रहा है और इस दिशा में निवेश कर रहा है। डिजिटल बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य एवं कृषि से जुड़े विषयों में भारत ने अनूठी उपलब्धियाँ हाँसिल की हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध मधुर हैं। दोनों देश तेल-गैस के व्यापार के अलावा रणनीतिक भागेदारी और प्रवासी कामगारों को लेकर भी करीब से जुड़े हैं।

भारत की चुनौतियाँ

भारत के सामने चुनौतियाँ भी हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध से विश्वभर में ऊर्जा और खाद्य संकट खड़ा हो रहा है। विश्व के कई देशों को मंदी का डर सता रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसी महाशक्तियाँ भी चिंतित हैं। व्यापार की चुनौतियों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण का संकट भी काफी बड़ा है। भारत-रूस के बीच में रक्षा और व्यापार संबंधी अत्यंत सशक्त संबंध रहे हैं। इंडानेशिया में जी-20 की समिट के समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भेंट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्याओं का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नगण्य हुई है, उस शून्य को भरने का काम भी जी-20 करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है उस पर पूरा विश्व अपनी दृष्टि लगाये है। क्योंकि भारत विश्व की ग्रोथ का इंजन बनने की ताकत रखता है। रूस-यूक्रेन युद्ध मसले पर भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसने अमेरिका के दबाव में आए बिना रूस से सस्ता तेल खरीदा क्योंकि भारत को अपनी जनता के हित पहले देखने हैं। अमेरिका और उसके मित्र देश रूस पर प्रतिबंधों का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह भारत का आत्मविश्वास एवं दृढ़ता ही है जहाँ से दुनिया को अपनी सोच बदलने एवं विश्व को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने की सोच को बल मिल रहा है।

उपसंहार

विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं अंतरिक्ष विज्ञान के साथ- साथ भारतीय दर्शन, संस्कृति, जीवन मूल्य, गौरवशाली परंपराएँ और मजबूत होती अर्थव्यवस्था विश्व के आकर्षण का केंद्र है। भारत की जिम्मेदारी है कि विश्व को बेहतर करके दिखाएँ और अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से दुनिया को परिचित कराते हुए अपने उच्च शैक्षिक मापदंडों के साथ सेवा परमोधर्म: की भावना को और मजबूत करें। भारत का दायित्व है कि अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें और इस अवसर को चुनौती के रूप में लेकर दुनिया को नये भारत से परिचित कराएँ। आजादी के इस अमृतकाल में जी-20 का नेतृत्व हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव बढ़ाने वाला है। समृद्ध ज्ञान परंपरा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत अपने को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का एक स्वर्णिम अवसर पाया है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास चुनौतियों से संबंधित समाधान है। भारत डिजिटल तकनीक में भी एक बड़ी शक्ति बनने के साथ विश्व के समक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा शीघ्र हो इसके लिए नीति-नियंत्ताओं को अपने दायित्व का पालन करते समय सचेत रहना होगा। भारत का कद और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे इसके लिए जनता को भी अपने हिस्से की भूमिका निभानी होगी। जी-20 की अध्यक्षता से भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त-समृद्ध आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा। ❑

(लेखक अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में सहायक आचार्य एवं उत्तर प्रदेश जी-20 के एम्बेसडर हैं।)

संदीप जोशी
व्याख्याता
रेवत, जिला जालोर
सदस्य NCTE

देशप्रेम के संस्कार देता भारत माता नमन स्थल

2005 के मार्च माह में मैंने शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। 15 अगस्त 2005, स्वाधीनता दिवस... आजादी का दिन। शिक्षक के नाते यह पहला राष्ट्रीय पर्व था।

नई पीढ़ी के शिक्षक के नाते कुछ नया करने का संकल्प तो पहले से मन मे था। यह संकल्प क्यों था, इसके अनेक कारण थे। परिवार के संस्कार भी और आसपास के परिवेश का प्रभाव भी। इस संकल्प के पीछे का कारण यह भी था कि बीएड की पढ़ाई के दौरान हमारे एक पूरा पेपर था जिसका नाम था- उदयमान भारतीय समाज में शिक्षा। इसका अध्ययन करते-करते मन में यह बात स्थायी रूप से बैठ गई कि देश में विद्यमान अनेक समस्याओं का समाधान तब होगा जब नागरिकों की देश के प्रति अच्युत निष्ठा होगी और देश के प्रति यह गहरी निष्ठा का भाव जागृत करने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। देश और संसार के सामने मौजूद सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा से निकलेगा। खैर, इस सैद्धांतिक विषय को छोड़कर जो प्रत्यक्ष है, उसकी चर्चा करते हैं। संस्कृत साहित्य में कहा गया है- ज्ञानं भार: क्रियां विना। केवल विजन पर्याप्त नहीं, एक्शन की भी आवश्यकता रहती है। तो इस पहले स्वतंत्रता दिवस पर कुछ नया, कुछ सार्थक, कुछ प्रेरणादायी कार्य करने का निर्णय किया।

विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व पर जहाँ ध्वजारोहण होता था, उस स्थान के नीचे ही विद्यार्थियों को साथ लेकर ईंटो की एक चौकी बनाई। उसमें मिट्टी भर कर उस पर पानी का छिड़काव किया, प्लाई के टुकड़े से मिट्टी को अच्छी प्रकार जमाया, दबाया। फिर इस चौकी पर भारत का नक्शा बनाया। भारत के नक्शे के अलावा शेष सारी मिट्टी खुरपी से खुरच कर हटा दी। सामने तैयार था भारत का उभरा हुआ शानदार नक्शा। रंगोली के रंगों से इसे सजाया गया। एक सुंदर कलाकृति तैयार हो गई। इसे आप सेंड आर्ट भी कह सकते है। देखने के बाद पूरे स्टाफ को यह मामला जंच गया।

इस नक्शे के पृष्ठ भाग में भारत माता का एक बड़ा चित्र भी लगाया। विद्यालय में उपलब्ध सारे महापुरुषों के चित्र भी नक्शे पर सजाए गए। विद्यालय परिवार ही नहीं, सभी आगन्तुकों के लिए यह रचना आकर्षण का केंद्र बन गई।

15 अगस्त, आजादी वाला दिन आ गया। जो बच्चे पीटी, परेड, पिरामिड या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे थे, एक तरह से उत्सव के प्रति उदासीन से थे, उन एक्स्ट्रा एक्टिव 'छंटे हुए' विद्यार्थियों को साथ लिया। उन्हें कार्यक्रम की पूरी योजना समझाई। कुछ नया काम हो रहा है इसलिए उत्सुकता के साथ ही विद्यार्थी इस नए काम में सक्रियता से जुड़े। विद्यालय के मुख्य द्वार

से लेकर कार्यक्रम स्थल तक ये 'छंटे हुए' विद्यार्थी कतारबद्ध खड़े किए गए। सबके हाथों में फूलों से भरी प्लेट। हर आगंतुक को हाथ में थोड़े फूल दिए गए। पंक्ति का अन्य विद्यार्थी उन्हें आगे का रास्ता बताता।

राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर विद्यालय आने वाले सब आगंतुकों ने उन फूलों से भारत भूमि का पूजन किया। क्योंकि विद्यालय में और गाँव में यह पहली बार हुआ था, अत: सभी के मन में स्वाभाविक उत्सुकता थी। आगंतुकों के मन में इस बात का भी संतोष था कि विद्यालय जाने के बाद उनकी भूमिका केवल दर्शक की ही नहीं है। राष्ट्रीय पर्व पर उनके पास भी करने के लिए कुछ काम है। सभी ग्राम वासियों ने स्त्रियों और पुरुषों ने बड़ी श्रद्धा के साथ में जमीन पर बने हुए भारत के मानचित्र पर अपने पुष्प अर्पित किए और देश के प्रति अपना अपनत्व महसूस किया। इससे उनके मन में राष्ट्रीय पर्व के प्रति भी श्रद्धा और क्रियाशीलता के भाव में बढ़ोतरी हुई।

धीरे-धीरे यह सिलसिला चल पड़ा।

लगातार हर वर्ष .....

साल में दो बार, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन।

15 अगस्त 2005 से 15 अगस्त 2020 तक। शिक्षक के रूप में काम करते हुए 18 वर्ष हो गए, यह क्रम और कर्म अभी जारी है। हर बार कुछ नवीनता लिए नक्शा बनने लगा।

कभी रंगोली के रंग तो कभी फूलों की सजावट। कभी भारत के पर्वत दर्शाए गए तो कभी नदियों का प्रवाह। कभी हर विद्यार्थी द्वारा घर से दीपक लाकर भारत माता की वंदना की गई तो किसी वर्ष सब गाँव वालों ने मिलकर बड़े धूपिये से भारत भूमि की महाआरती उतारी।

सिलसिला अभी जारी है।

10 वर्ष बाद मेरा स्थानांतरण सामतीपुरा से गोदन हो गया। मगर राष्ट्रीय पर्व पर भारत भू वंदन का यह क्रम जारी रहा। नई स्कूल में भी पहली बार यह आयोजन हुआ। वहीं पुरानी स्कूल में भी शिक्षक साथियों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने यह कार्यक्रम लगातार जारी रखा। अच्छी जनसहभागिता एवं वर्षों तक लगातार आयोजन करते रहने के कारण अब यह आयोजन व्यापक भी हुआ है। अब तो और भी कई मित्रों ने अपने विद्यालयों में यह परंपरा शुरू कर दी है।

हम जब किसी काम में मन से डूबते हैं तो उस काम के बारे में स्वत: ही मन में नई-नई कल्पनाएँ आने लगती हैं, नए-नए विचार प्रकट होने लगते हैं। जैसे किसी कवि के मन में कविताएँ प्रस्फुटित होती हैं, वैसे ही किसी काम में डूबने के बाद उसके संबंध में आगामी आइडिया, विचार स्वत: प्रकट होते जाते हैं।

गोदन का विद्यालय एकदम मुख्य मार्ग पर स्थित है और चारदीवारी भी बहुत छोटी है। आसानी से कोई भी कूद कर अंदर आ सकता है। यहाँ आने के बाद पहला राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी का आया। मुझे विद्यालय में आए अभी महीना भर ही हुआ था। संस्था प्रधान जी से अनुमति लेकर विद्यार्थियों के सहयोग से मिट्टी में भारत का नक्शा बनाना शुरू किया। सामतिपुरा की तुलना में यहाँ पर एक प्रयोग और जोड़ दिया। इस बार चौकी बनाकर उसे गोबर से लीप दिया। इससे चौकी की मजबूती बढ़ गई। फिर इस पर चॉक से भारत का नक्शा बनाकर आसपास की शेष मिट्टी काट दी गई। इससे नक्शा मजबूत और अधिक आकर्षक बन पड़ा। जिस समय यह कार्य चल रहा था, स्टाफ के कुछ मित्र आत्मीयता पूर्वक हँस रहे थे कि सर आपका पहले वाला विद्यालय एक प्रकार से पूरी चारदीवारी का और लॉक एण्ड की विद्यालय था, इसलिए वहाँ यह संभव था। अपना यह गोदन विद्यालय तो ऑन रोड स्कूल है। छुट्टी के बाद भी बच्चों का जमघट लगा रहता है। बाउंड्री भी बहुत छोटी है। 26 जनवरी तक तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने हँसकर उत्तर दिया कि नहीं भी मिलेगा तो क्या है? अपना इसमें कुछ भी आर्थिक निवेश तो है नहीं। मिट्टी ही तो है, वापस बना लेंगे। ऐसे ही सामान्य हँसी मजाक चलता रहा।

अच्छा, सुंदर, आकर्षक मानचित्र तैयार हो गया। 26 जनवरी की प्रात: तक एकदम सुरक्षित रहा। किसी ने भी उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। पूर्व अनुसार ही रंगोली के रंगों, फूलों के द्वारा साज-सज्जा की गई विद्यालय में मौजूद सारे महापुरुषों

के चित्र लाए गए इस नए स्थान पर भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ में सभी विद्यार्थियों ने, स्टाफ साथियों ने, ग्राम वासियों ने राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर भारत माता पूजन, राष्ट्रीय ध्वज वंदन का आयोजन किया। यह पहले वाले से बड़ा गाँव था, इसलिए लोग भी अच्छी संख्या में आए । यहाँ आते आते लोगों के जीवन के सफर में मोबाइल सेल्फी वाला पॉइंट भी जुड़ गया था। सबने इस मानचित्र के पास में खूब फोटो खिंचवाई, खूब सेल्फी ली।

विद्यार्थियों के मन को भाया यह नवाचार

पिछले विद्यालय में यह आयोजन सामान्यतया 26 जनवरी और 15 अगस्त के विशेष अवसरों पर ही होता था, किंतु गोदन में विद्यार्थियों को यह भूमि पर बना भारत का नक्शा इतना भाया कि उन्होंने लगभग 2 महीने तक रोज इसकी सजावट की। बिना किसी के कहे, बिना किसी के बतलाए। बिना किसी बाह्य प्रेरणा के स्वत:स्फूर्त..... एकदम सहज तरीके से प्रतिदिन भारत के मानचित्र की साफ सफाई करना और अलग-अलग प्रकार से इसका साज-सज्जा करना। सामान्यतया रंगो एवं फूलों से ही सजावट करते थे। कई बार नया प्रयोग भी कर देते थे। भारत की पूरी सीमा पर दीपक लगाना, फलों और सब्जियों से नक्शे को सजाना, अलग-अलग प्रकार के गुब्बारों से सजाना, गेहूँ, चावल और मूंग के द्वारा सजावट करना ऐसे अनेक प्रयोग छात्र-छात्राओं ने अपने मन से किए। यहाँ मानचित्र वाली चौकी गोबर से लीपी हुई थी, इसलिए लंबे समय तक बनी रही। ग्रीष्म अवकाश की समाप्ति के समय हुई बरसात के कारण से यह कुछ क्षत-विक्षत हो गई।

परंतु अगले राष्ट्रीय पर्व (15 अगस्त) से पहले ही, 9-12 अगस्त तक गोदन स्थित मेरे विद्यालय में जिला स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता (टूर्नामेंट)का आयोजन था। एक बार फिर भव्य मानचित्र बना और सजा। हालाँकि बरसात ने हमारी बराबर परीक्षा ली। इन चार दिनों में तत्कालीन जिला प्रमुख डॉ. बन्ने सिंह जी, आहोर विधायक श्री शंकर सिंह जी, जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार जी सोनी, एक पुराने मित्र जो आजकल प्रोफेसर हैं- डॉ. भरत मेघवाल जी, उनके साथ आये एक विदेशी मित्र पोलेंड निवासी- डेनिश, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रभुदान जी राव, सरपंच निम्बाराम जी समेत अनेक गणमान्य जनों ने विद्यालय में भारत भूमि का वंदन, अभिनंदन किया।

एक सामान्य धारणा के विपरीत, सरकारी स्कूल के इस तरह के विशेष आयोजनों से सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई।

टूर्नामेंट के बाद 15 अगस्त को पुन: राष्ट्रीय पर्व पर यह आयोजन हुआ। गोदन में यह दूसरा ही अवसर था। ग्रामवासियों ने खूब फोटो और सेल्फी ली। सब खुश थे। हम सब भी खुश क्योंकि इस दृश्य को देखकर अनेक लोगों के मन में देशभक्ति के भाव हिलोरे ले रहे थे। यही तो उद्देश्य होता है इस सारी मेहनत का।

हम जब किसी काम में मन से डूबते हैं तो उस काम के बारे में स्वत: ही मन में नई-नई कल्पनाएँ आने लगती हैं, नए-नए विचार प्रकट होने लगते हैं। जैसे किसी कवि के मन में कविताएँ प्रस्फुटित होती हैं, वैसे ही किसी काम में डूबने के बाद उसके संबंध में आगामी आइडिया, विचार स्वत: प्रकट होते जाते हैं।

चूंकि यह मानचित्र खुले में बना हुआ था, इसलिए बारिश के दौरान इसका भी बिगड़ना, टूटना स्वाभाविक था। विद्यार्थियों ने 26 जनवरी से लेकर छुट्टियाँ पड़ने तक बहुत मन से इसका शृंगार किया था, इसलिए उनका भी जुड़ाव बना हुआ था और बारिश में गीला होने के कारण नक्शा बार-बार बिगड़ जाता। इससे बच्चे और उनके साथ हम शिक्षक भी, दोनों दुखी थे। इसी उहापोह में एक नया विचार आया।

और इस नए विचार की कल्पना 2005 में जब यह कार्यक्रम शुरू किया था, तब बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे विचार-विमर्श के बाद इसी स्थान पर भारत का स्थायी पक्का सीमेंटेड मानचित्र बनाने का निर्णय लिया गया। कारीगर को बुलाकर उसे यह विचार समझाया गया। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई का विचार करके एक रैंप बनाया गया जैसा कि अनेक सरकारी भवनों में होता है। इस रैम्प पर मानचित्र बनाना था। पहले तो मिट्टी का मानचित्र था, इसलिए सीमाएँ थोड़ी आगे पीछे होने पर चल जाती थी। किन्तु सीमेंटेड मानचित्र तो एकदम त्रुटि रहित ही होना चाहिए। इसलिए विचार शुरू हुआ। सामाजिक के शिक्षक श्री शंकरलाल जी मेघवाल ने यह कार्य अपने जिम्मे लिया। उन्होंने रेम्प पर चौक द्वारा वर्गाकार खाने बनाकर पैमाना मानते हुए मानचित्र बनाया। एकदम हूबहू... इस मानचित्र की सीमाओं को चॉक के द्वारा दो-तीन बार गहरा किया। अभी भारत को रैंप के धरातल से कुछ ऊपर लेना था इसलिए